epaper.dehatsandesh.com

3 उपायुक्त ने श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा तीर्थयात्रियों के जत्थे का स्वागत किया

5 कनाडियन ओपन 2025: 14 डबल फाल्ट के बावजूद कोको गाफ प्री क्वार्टरफाइनल में

8 ब्रोकली की खेती

न्यूनतम 25

मौसम जम्मू

अधिकतम 29

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

देहात संदेश

वर्ष-22, जम्मू तवी, अंक-190 | जम्मू तवी, शनिवार 02 अगस्त, 2025 | मूल्य-3 रूपये- (लेह)4 रूपये | पृष्ठ -8

जम्मू-कश्मीर में एमबीबीएस सीटें बढ़ीं, लद्दाख को मिला पहला मेडिकल कॉलेज

श्रीनगर, 1 अगस्त। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए एमबीबीएस सीटों का राज्यवार आँकड़ा जारी किया है, जिससे जम्मू-कश्मीर में चिकित्सा शिक्षा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि और लद्दाख के लंबे समय से प्रतीक्षित समावेश का पता चलता है।

आँकड़ों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में एमबीबीएस सीटों की क्षमता 2020-21 में 1,135 से बढ़कर 2024-25 में 1,385 हो गई है, जिससे पाँच वर्षों में 250 नई सीटें जुड़ी हैं।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जहाँ अब तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, को पहली बार 100 एमबीबीएस सीटें आवंटित की गई हैं। समाचार एजेंसी के अनुसार, इस क्षेत्र में लंबे समय से डॉक्टरों की कमी को दूर करने और उच्च-ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिए एक मेडिकल कॉलेज की माँग की जा रही थी।

अधिकारियों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में सीटों की संख्या में वृद्धि नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत मौजूदा संस्थानों के विस्तार का परिणाम है।

एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मज़बूत करने और डॉक्टर-रोगी अनुपात को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए कुल एमबीबीएस सीटों के मामले में, जम्मू-कश्मीर 1,385 सीटों के साथ सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 21वें स्थान पर है।

यह इसे झारखंड, हिमाचल प्रदेश और मेघालय जैसे छोटे या पूर्वोत्तर राज्यों से ऊपर मध्य-स्तरीय श्रेणी में रखता है, लेकिन कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे अग्रणी राज्यों से काफी पीछे है।

भारत ने पाकिस्तान से अवैध रूप से कब्ज़ा किए गए पीओके को खाली करने का आह्वान दोहराया

नयी दिल्ली, 01 अगस्त। पाकिस्तान ने भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है और नई दिल्ली ने इस्लामाबाद से लगातार अपने अवैध और जबरन कब्ज़े वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आह्वान किया है, सरकार ने शुक्रवार को संसद को सूचित किया।

विदेश मंत्रालय से लोकसभा में पूछा गया कि क्या हमारे कश्मीर, जिसे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहा जाता है, के कुछ हिस्से अभी भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं और उन्हें वापस पाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं।

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, पाकिस्तान ने भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है। भारत सरकार ने लगातार पाकिस्तान से अपने अवैध और जबरन कब्ज़े वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने

का आह्वान किया है।

उन्होंने आगे कहा, भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है और इन कब्ज़े वाले क्षेत्रों में ठोस बदलाव लाने के उसके सभी प्रयासों को अस्वीकार करती है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत का यह दृढ़ और सैद्धांतिक रुख रहा है कि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग रहे हैं, हैं और हमेशा रहेंगे।

राज्य मंत्री ने कहा कि भारतीय संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित 1994 के प्रस्ताव में भी इसकी पुष्टि की गई थी।

मंत्रालय से यह भी पूछा गया कि नक्शे में पीओके को कैसे दर्शाया गया है।

उन्होंने कहा, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आधिकारिक मानचित्र स्पष्ट रूप से पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को, जिसमें पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्ज़ा किए गए क्षेत्र भी शामिल हैं, भारत संघ के हिस्से के रूप में दर्शाते हैं।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, सिंह ने कहा, भारत ने आतंकवाद की जड़ों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने, किसी भी प्रकार के ब्लैकमेल को बर्दाश्त न करने और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए निर्णायक कदम उठाने के अपने दृष्टिकोण को भी स्पष्ट किया है।

विदेश मंत्रालय ने अप्रैल-मई 2025 में हुई सैन्य झड़पों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे गए प्रश्न का भी उत्तर दिया।

उन्होंने कहा, आतंकवाद को किसी भी प्रकार के राजनयिक संपर्क के साथ असंगत मानने पर भारत का रुख भी उच्चतम स्तर पर बता दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है।

उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को, अधिसूचना सात अगस्त को होगी जारी

नयी दिल्ली, 01 अगस्त। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को कराया जायेगा। इसके लिए अधिसूचना अगले सप्ताह गुरूवार को जारी की जायेगी।

चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना गुरुवार, 07 अगस्त को जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

नामांकन पत्र गुरुवार, 21 अगस्त तक भरे जा सकेंगे और नामांकन पत्रों की जांच शुक्रवार 22 अगस्त को की जाएगी। नामांकन सोमवार, 25 अगस्त तक वापस लिए जा सकेंगे।

आयोग ने कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो मतदान मंगलवार, नौ सितंबर को पूर्वाह्न दस बजे से शाम पांच बजे तक कराये जायेंगे। मतगणना उसी दिन मतदान सम्पन्न होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी की निगरानी में करायी जाएगी। सभी के मत का मूल्य एक समान (1) होगा।

आयोग ने राज्य सभा के महासचिव प्रमोद चन्द्र मोदी को इस चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है।

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के निर्वाचक मंडल में राज्य सभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य तथा लोक सभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। आयोग ने निर्वाचक मंडल की सूची पहले ही तैयार कर ली है जिसमें कुल 788 सदस्यों के नाम हैं ।

निर्वाचक मंडल में राज्य सभा के 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य और लोक सभा के 543 सदस्यों के नाम हैं। राज्य सभा में इस समय पांच सीटें और लोक सभा में एक सीट रिक्त है।

श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराया जा रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ को टाला

- भारत-अमेरिका साझेदारी कई बदलावों और चुनौतियों से गुजरकर और मजबूत हुई
- अमेरिकी टैरिफ पर बोले अधिकारी, किसानों, डेयरी और कृषि उद्योग के हितों से किसी कीमत पर समझौता नहीं करेगी सरकार

वॉशिंगटन/नई दिल्ली, 1 अगस्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत से आयातित वस्तुओं पर लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है। अब यह टैरिफ 1 अगस्त की बजाय 7 अगस्त से प्रभावी होगा। डोनाल्ड

ट्रंप ने भारत समेत 92 देशों पर नए टैरिफ लगा दिए हैं। ये 7 अगस्त से लागू होंगे। इसमें भारत पर 25 फीसदी और पाकिस्तान पर 19 फीसदी टैरिफ लगाया गया है। साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगाया गया है; पहले ये 29 फीसदी था। वहीं दुनियाभर में सबसे ज्यादा टैरिफ सीरिया पर लगाया गया है, जो 41 प्रतिशत है। लिस्ट में चीन का नाम शामिल नहीं है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनियाभर के देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन 7 दिन बाद ही इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया था। कुछ दिनों बाद 31 जुलाई तक का समय दिया था। फिर 90 दिनों में 90 सौदे कराने का टारगेट रखा गया था। हालांकि इस बीच अमेरिका का महज 7 देशों से समझौता हो पाया। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नए टैरिफ की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, भारत हमेशा से रूस से अधिकांश सैन्य आपूर्ति खरीदता आया है और अब चीन के साथ मिलकर रूस से ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है।

भारत और रूस के बीच मजबूत और भरोसेमंद साझेदारी : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 अगस्त। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत और रूस के बीच मजबूत और भरोसेमंद साझेदारी है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत का किसी भी देश के साथ संबंध अपनी खूबियों पर टिका है और इसे किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत-रूस संबंधों में कोई बदलाव आया है। इस सवाल के जवाब में जायसवाल ने कहा, हमारे किसी भी देश के साथ संबंध अपनी योग्यता पर आधारित हैं और उन्हें किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। जहां तक भारत-रूस संबंधों का सवाल है, हमारे बीच की दोस्ती मजबूत और भरोसेमंद है।

रणधीर जायसवाल की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के उस बयान के 24 घंटे बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत का रूस से तेल खरीदना अमेरिका के साथ उसके रिश्तों में परेशानी का कारण है। गौरतलब है कि भारत 2022 से शुरू हुए रूस-यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है। रूबियो ने गुरुवार को फॉक्स रेडियो पर कहा, भारत हमारा सहयोगी और रणनीतिक साझेदार है, लेकिन विदेश नीति में हर समय 100 प्रतिशत सहमति नहीं होती। उन्होंने आगे कहा, भारत की ऊर्जा जरूरतें बहुत ज्यादा हैं और इसमें तेल, कोयला, गैस और अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जरूरी चीजें खरीदने की क्षमता शामिल है, जैसा हर देश करता है।

'तत्काल मरम्मत कार्यों' के कारण अमरनाथ यात्रा 3 अगस्त तक स्थगित

जम्मू कश्मीर, 1 अगस्त । अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुक्रवार को 3 अगस्त तक स्थगित कर दी गई। यात्रा के दोनों मार्गों पर तत्काल मरम्मत और रखरखाव कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह पहलगाम मार्ग से तीर्थयात्रा स्थगित रही और तीर्थयात्रियों के किसी नए जत्थे को गुफा मंदिर जाने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि बालटाल मार्ग से यात्रा की अनुमति दी गई। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण बाद में बालटाल मार्ग से भी यात्रा स्थगित कर दी गई। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों की आवाजाही लगातार दूसरे दिन भी स्थगित रही। कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार बिधूड़ी ने कहा,

हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण, श्री अमरनाथ जी यात्रा मार्ग के बालटाल मार्ग पर मरम्मत और रखरखाव कार्य किए जाने की आवश्यकता है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर, 3 अगस्त को बालटाल मार्ग से भी यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आगे की जानकारी समय आने पर जारी की जाएगी। बिधूड़ी ने कहा कि यात्रा क्षेत्र में पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर हाल ही में भारी बारिश हुई है, इसलिए इस भारी बारिश के बाद बालटाल मार्ग पर तत्काल रखरखाव कार्य किए जाने की आवश्यकता है। कश्मीर में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कें असुरक्षित हो गई थीं, जिसके बाद बुधवार को बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर तीर्थयात्रा स्थगित कर दी गई थी।

जम्मू-कश्मीर में 5,447 पंजीकृत आयुष चिकित्सक हैं

श्रीनगर, 1 अगस्त। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत एक उत्तर के अनुसार, 1 जनवरी, 2023 तक जम्मू-कश्मीर में कुल 5,447 पंजीकृत आयुष चिकित्सक हैं।

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने कहा कि आयुष चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की है, क्योंकि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है।

उत्तर में जम्मू-कश्मीर में डॉक्टरों की अनुमानित कमी के अलग से आंकड़े नहीं दिए गए।

यद्यपि केंद्र सीधे तौर पर भर्ती या कर्मचारियों को बनाए रखने का प्रबंधन नहीं करता है, लेकिन वह आयुष्यन योजना के तहत क्षमता निर्माण का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) के माध्यम से आयुष चिकित्सकों की व्यावसायिक क्षमता को उन्नत करना है।

केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पूरे भारत में पंजीकृत 7.5 लाख आयुष चिकित्सकों का हिस्सा है।

उमर अब्दुल्ला की यह यात्रा एकता का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली/जम्मू, 1 अगस्त मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुजरात दौरे पर हैं, उन्होंने अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट की तारीफ की। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी यह यात्रा एकता का महत्वपूर्ण संदेश देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम उमर अब्दुल्ला के सोशल मीडिया पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा कि कश्मीर से केवड़िया। उमर अब्दुल्ला को साबरमती रिवरफ्रंट पर दौड़ते और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाते देखकर बहुत अच्छा लगा। उनकी यह यात्रा एकता का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है और हमारे साथी भारतीयों को भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगी। इससे पहले जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एक पर्यटन कार्यक्रम के लिए अहमदाबाद में रहते हुए मैंने यहां होने का फायदा उठाते हुए प्रसिद्ध साबरमती रिवरफ्रंट सैरगाह पर सुबह की दौड़ लगाई। यह उन सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जहां मैं दौड़ पाया हूं और इतने सारे अन्य पैदल यात्रियों व धावकों के साथ इसे साझा

करना मेरे लिए खुशी की बात थी। मैं अद्भुत अटल फुट ब्रिज के पास से भी दौड़कर गुजरने में कामयाब रहा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखकर कहा, मैंने सोचा नहीं था कि यह प्रतिमा इतनी भव्य होगी।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की अदालतों में 3.8 लाख मामले लंबित

श्रीनगर, 1 अगस्त। संसद में प्रस्तुत नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की विभिन्न अदालतों में कुल मिलाकर 3.8 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। 1 अगस्त, 2025 को विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दिए गए लिखित उत्तर के अनुसार, जम्मू-कश्मीर की जिला और अधीनस्थ अदालतों में 3,35,513 मामले लंबित हैं, जबकि लद्दाख की अदालतों में 1,417 मामले लंबित हैं। 28 जुलाई, 2025 तक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में कुल 45,296 मामले लंबित हैं। समाचार एजेंसी के अनुसार, सरकार ने अपने जवाब में कहा कि वह न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों के मुद्दे से अवगत है। यद्यपि मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, सरकार ने कहा कि वह आवश्यक संसाधन, अवसंरचनात्मक सहायता और नीतिगत हस्तक्षेप प्रदान करके न्याय वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मामलों में देरी को दूर करने और उनके शीघ्र निपटारे के लिए, सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कई पहलों का हवाला दिया। इनमें अगस्त 2011 में न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना शामिल है

अब ट्रंप का अध्याय बंद, प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया स्पष्ट, ऑपरेशन सिंदूर में किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया : आजाद

नई दिल्ली, 1 अगस्त। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डी.पी.ए.पी) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका निभाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जवाब के बाद अब ट्रंप का अध्याय बंद हो गया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के डीजीएमओ द्वारा भारत के डीजीएमओ से हुई बातचीत के बाद ऑपरेशन को स्थगित करने का फैसला लिया गया। लेकिन, उससे

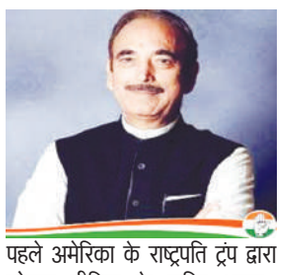

पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया के जरिए भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा की बात कही गई और साथ ही इसके लिए मध्यस्थता की बात भी लिखी गई। इसके बाद तमाम मौकों पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर में अपनी मध्यस्थता की बात कही। जिसके बाद भारत में विपक्षी दल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा से सवाल कर रहे थे कि किसी अन्य देश की मध्यस्थता से सीजफायर की घोषणा क्यों हुई। विपक्षी दल के सदस्य इसको लेकर पीएम मोदी से जवाब मांग रहे थे, जबकि केंद्र सरकार के आला अधिकारी, सेना के आला अधिकारी और मंत्रियों की तरफ से कई बार स्पष्ट किया गया की पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने सीजफायर का फैसला लिया। विपक्ष फिर भी इसे मानने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद पीएम मोदी ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी चर्चा में अपने संबोधन के दौरान स्पष्ट कर दिया कि इस सीजफायर के फैसले में किसी देश ने मध्यस्थता नहीं की। इसी को लेकर गुलाब नबी आजाद ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में स्पष्ट रूप से कह दिया कि विश्व के किसी भी देश के नेता ने ऑपरेशन सिंदूर में हस्तक्षेप नहीं किया। साथ ही उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भी जिक्र किया, इसलिए अब यह अध्याय बंद हो गया।

राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, सोमवार तक के लिए कार्यवाही स्थगित

नई दिल्ली, 1 अगस्त। राज्यसभा में शुक्रवार को भी हंगामा हुआ, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्ष के कई सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के गहन रिव्यू का मुद्दा उठाते हुए इस पर चर्चा की मांग की। सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद ही इस मांग को लेकर सदन में हंगामा व नारेबाजी शुरू हो गई। वहीं, विपक्ष के कई सांसद अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर भी सदन में चर्चा चाहते थे। विपक्षी सांसदों ने नियम 267 के तहत इन मुद्दों पर चर्चा की मांग की। जिसे उपसभापति ने अस्वीकार कर दिया। इससे नाराज विपक्षी सांसदों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा होने पर सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा जिसके चलते सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के कुछ देर बाद उपसभापति ने बताया कि विपक्ष के 28 सांसदों ने उन्हें विभिन्न मुद्दों पर नियम 267 के अंतर्गत चर्चा के लिए नोटिस दिए हैं। नियम 267 के अंतर्गत सदन के अन्य सभी कार्यों को स्थगित करके दिए गए विषयों पर चर्चा कराई जाती है और चर्चा के अंत में वोटिंग का प्रावधान होता है। डॉ. सस्मित पात्रा, सुलता देव, सुभाशीष खुंटिया, निरंजन बिशी, मानस रंजन समेत कई अन्य विपक्षी सांसदों ने उड़ीसा में गंभीर अपराधों, महिलाओं

व गर्ल चाइल्ड के साथ होने वाले अपराधों पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की। वहीं, नीरज डांगी, अखिलेश प्रसाद सिंह, सुष्मिता देव, संजय सिंह, राजीव शुक्ला, साकेत गोखले व रेणुका चौधरी समेत कई अन्य सांसद बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन रिव्यू के मामले पर चर्चा की मांग कर रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के रीतीब्रता बनर्जी, सागरिका घोष व डीएमके के तिरुचि आदि सांसदों ने देश के विभिन्न हिस्सों में पश्चिम बंगाल के कामगारों के साथ भेदभाव की बात कहते हुए इस पर चर्चा की मांग की।

नहीं आया इंटरव्यू के लिए कॉल, आपने की होंगी ये 5 गलतियां

शायद आप कुछ समय से जॉब तलाश रहे हों और आपने अलग-अलग कंपनियों, अलग-अलग पदों पर आवेदन दिया हो। हर दिन आप यह काम करते हो लेकिन आपके पास अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हो, ना कोई कॉल, ना ई-मेल। आपके हताश होने से पहले, यहां कुछ जरूरी बातें दी जा रही है जो कि आप आवदेनों को भेजने के पहले एक बार फरि चेक कर लें।

हर आवेदन में एक ही सीवी और कवर लेटर तो नहीं यूज किया

हर जॉब अलग है और उस जॉब की जरूरत के हिसाब से सीवी में बदलाव की जरूरत होती है। आपको अपना सीवी कस्टमाइज करने के लिए समय निकालना चाहि और यह सोचना चाहिए कि ऐसा क्या बदलाव किया जाए कि आपको इंटरव्यू के लिए एचआर से कॉल आ जाए। अगर आपका सीवी हर जॉब के हिसाब से पर्सनलाइज्ड नहीं हुआ तो यह इग्नोर हो सकता है। एम्प्लॉयर्स यह बात नोटिस करते है कि आपके सीवी और कवर लेटर में एक ही बातें तो नहीं है। भीड़ से अलग दिखने के लिए आपको यह साबित करना होगा कि आप एक अच्छे एम्प्लॉई बन सकते हैं। ऐसी चीजें शामिल करें जिससे कंपनी ज्यादा आकर्षित हो।

आवेदन गलत जगह तो भेज नहीं दिया

जिस व्यक्ति को आवदेन भेजना है उसके नाम में कई आवेदक गलती से या मूर्खतावश गलती कर देते हैं। वशिष रूप से जब आप अलग-अलग जगहों पर अप्लाई कर रहे हैं तो एड्रेसी और कंपनी का नाम अपडेट करना आसानी से भूल सकते हैं। इतना ही नहीं नाम की स्पेलिंग में गलती भी भारी पड़ सकती है।

आप न्यूनतम योग्यता पर खरे नहीं उतरे हैं

आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा अगर आप अंडरक्वॉलिफाइड हैं। अगर आपके पास आवश्यकतानुसार अनुभव, शैक्षणिक योग्यता नहीं है या आपने उसी माहौल या इंडस्ट्री में काम नहीं किया है तो आपका सीवी बाहर कर दिया जाएगा।

याद रखें, आपको यह पता होना चाहिए कि आप योग्य है लेकिन आप रिकूटर के लिए केवल एक कागज का टुकड़ा हैं। वे आपके बारे में उतना ही जानते हैं जो आपका पिछला अनुभव कहता है। उन्हें कई सारे सीवी देखने होते हैं और वे कभी भी अपना समय ऐसे में व्यर्थ नहीं करेंगे या आपके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करेंगे।

क्या आप न्यूनतम योग्यता को पार कर गए हैं

अगर आप ओवरक्वॉलिफाइड हैं तो भी आपके पास कॉल नहीं आएगा। कोई भी कंपनी ऐसे व्यक्ति को हायर नहीं करेगी। ऐसे में आपका सीवी भी रिजेक्ट हो जाएगा और वे सीवी के ढेर में नए आवेदन पर नजर घुमाएंगे।

कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपडेट किया

भेजने से पहले आपको सीवी आपको बार-बार चेक करना चाहिए। यह सुनिश्चित कर लें कि आपने आपका वर्तमान ई-मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर डॉक्यूमेंट्स में अपडेट कर लिया है। अगर आपने आपका पुराना सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिया है तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपने उसे सीवी से भी हटा दिया है। अगर आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में प्राइवेसी सेंटिंग कर रखी है तो एचआर को इसके जरिए संपर्क करने का मत कहिए।

भारत में मैनेजमेंट में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के बीच एमबीए इन मार्केटिंग हमेशा से एक लोकप्रिय स्पेशलाइजेशन रहा है। मगर अब डिजिटल युग के आने से मार्केटिंग के क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव आया है और अब इसमें डिजिटल मार्केटिंग भी शामिल हो गई है।

अब डिजिटल मार्केटिंग में पा सकते हैं एमबीए डिग्री

पढ़ाई के क्षेत्र के रूप में डिजिटल मार्केटिंग का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा है कि अब मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग को एक ही माना जाने लगा है। यूं तो दोनों ही क्षेत्रों में मूल काम उत्पादों व सेवाओं का प्रमोशन तथा सेल्स है मगर डिजिटल मार्केटिंग में अपनाई जाने वाली रणनीतियां परंपरागत मार्केटिंग से बहुत अलग और कहीं अधिक प्रभावी होती हैं। डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र की बढ़ती लोकप्रियता और इसके लगातार विस्तार को देखते हुए मैनेजमेंट गुरुओं ने एमबीए कोर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन की अलग ब्रांच की जरूरत महसूस की। आज डिजिटल मार्केटिंग में एमबीए का विकल्प तो उपलब्ध है मगर कई विद्यार्थियों में इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति है कि मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है और वे इन दोनों में से किस स्पेशलाइजेशन का चयन करें। तो चलिए, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।

डिजिटल मार्केटिंग से कैसे अलग

जहां 'मार्केटिंग'' में सभी प्रकार की मार्केटिंग आती है, वहीं 'डिजिटल मार्केटिंग'' में केवल डिजिटल माध्यमों द्वारा की गई मार्केटिंग शामिल है। इनमें वेबसाइट, सोशल नेटवर्क, बैनर ऐड, गूगल ऐड, सर्च रिजल्ट, यूट्यूब वीडियो आदि आते हैं। परंपरागत मार्केटिंग में विज्ञापनदाता से उपभोक्ता की ओर सूचना का एकतरफा प्रवाह होता है। वहीं डिजिटल माकेटिंग में दोतरफा संवाद संभव है। परंपरागत मार्केटिंग में जहां विज्ञापन की लागत बहुत अधक आती है, वहीं डिजिटल मार्केटिंग में यह कम रहती है। परंपरागत मार्केटिंग कैंपेन काफी पहले से प्लान किए जाते हैं मगर डिजिटल कैंपेन तात्कालिक भी हो सकते हैं।

एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग

कई युवाओं का तर्क होता है कि केवल डिजिटल मार्केटिंग में एमबीए कर अपनी पढ़ाई का स्कोप सीमित करने के बजाय मार्केटिंग में एमबीए करना बेहतर है। यह बात अपनी जगह सही हो सकती है मगर आप जरा डिजिटल मार्केटिंग को भविष्य के नजरिये से भी देखें। पिछले एक दशक में सारे बिजनेस घरानों ने अपना ध्यान मार्केटिंग के परंपरागत माध्यमों से हटाकर डिजिटल माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। डिजिटल मार्केटिंग की लोकप्रियता के कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख हैं कम लागत, तत्काल प्रतिसाद, लचीलापन, सुविधा और प्रभावशीलता। कई जानकार तो यह भी कहते हैं कि आज के दौर में अगर आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग नहीं की, तो ग्राहक आपसे दूर ही रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में सारी मार्केटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर ही जाएगी। इस प्लेटफॉर्म पर खास तरह की मैनेजमेंट स्किल की जरूरत होती है। इसीलिए एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग एक बेहतर तथा आकर्षक करियर ऑप्शन बन गया है।

क्या है स्कोप

हमारे यहां अब भी यह फील्ड अपने शुरूआती दौर में है और इसके बड़ी तेजी से विस्तार लेने की उम्मीद है। डिजिटल मार्केटिंग में एमबीए के विद्यार्थियों को तकनीकी बुनियाद तथा डिजिटल लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स से रूबरू कराया जाता है। इसमें ये विषय भी शामिल होते हैं : वेब एनालिटिक्स, एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन, बायर बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बी2बी ई-मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आदि। भविष्य में इनमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजिन मार्केटिंग आदि के भी शामिल किए जाने की संभावना है।

पे-पैकेज

काफी नई फील्ड होने के बावजूद डिजिटल मार्केटिंग वेतन के लिहाज से बेहद आकर्षक है। एक नया डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर 4 से 5 लाख रुपए का वार्षिक पैकेज पा सकता है। अनुभव के साथ इसमें तीव्रता से वृद्धि होती है। 5 से 7 साल का अनुभवी डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर 10-12 लाख का वार्षिक पैकेज पा सकता है।

करियर ऑप्शन

डिजिटल मार्केटिंग में डिग्री लेने के बाद करियर के कई ऑप्शन खुले होते हैं। फिलहाल हम इनमें से 3 सबसे बेहतर ऑप्शंस की चर्चा करेंगे।

डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर

इन्हें मार्केटिंग की भाषा में 'बज क्रिएटर'' भी कहा जाता है। ये कस्टमर बिहेवियर डेटा पर काम करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग की ऐसी रणनीति तैयार करते हैं, जिससे उस उत्पाद या सेवा के प्रति उपभोक्ता की जिज्ञासा जागे। ईमेल मार्केटिंग, ईकॉमर्स, सोशल मीडिया कैंपेन आदि इनके काम का हिस्सा हैं। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के रूप में जॉब के अवसर अकेले इस साल ही 12 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के रूप में करियर बनाना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप कोडिंग, वेब डिजाइन, एप्लिकेशन डेवलपमेंट, मार्केटिंग इकोनॉमिक्स तथा जनरल मैनेजेरियल एप्टिट्यूड में पारंगत हो जाएं।

इंटरनेट मार्केटिंग मैनेजर

अगर आपमें डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग का हुनर है, तो आप इस फील्ड में करियर बना सकते हैं। इंटरनेट मार्केटिंग मैनेजर को मुख्य रूप से मार्केट रिसर्च एनालिस्ट के रूप में काम करना होता है। वे कस्टमर बिहेवियर डेटा का अध्ययन कर यह तय करते हैं कि उत्पाद या सेवा की बिक्री की कितना संभावना है। इसमें एमबीए की डिग्री के अलावा मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस में सर्टिफिकेशन आपके काम आएगा।

डिजिटल सेल्स मैनेजर

मार्केटिंग व सेल्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सो कई कंपनियां डिजिटल सेल्स की जिम्मेदारी डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोफेशनल को सौंपती हैं। यदि आपको डिजिटल मीडिया व निजता कानूनों, ब्राण्ड मैनेजमेंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आदि का ज्ञान है, तो डिजिटल सेल्स मैनेजर के रूप में यह आपको बहुत काम आएगा।

साइंस स्टूडेंट्स के लिए इस क्षेत्र में ढेरों हैं संभावनाएं

विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आए दिन नई-नई शाखाएं जुड़ रही हैं। नैनो टेक्नोलॉजी भी तुलनात्मक रूप से एक नया क्षेत्र है। नैनो टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर देश-विदेश में छलांगें लगाकर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी को 'साइंस ऑफ मिनिएचर' अर्थात लघुतर का विज्ञान भी कहा जाता है। जब कोई वस्तु या सामग्री नैनो डाइमेंशन (10-9 मीटर = 1 नैनोमीटर) में बदल जाती है, तो उसके भौतिक, रासायनिक, चुंबकीय, प्रकाशीय, यांत्रिक और इलेक्ट्रिक गुणों में बड़ा भारी परिवर्तन आ जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसा विषय क्षेत्र है, जिसमें नए अवसरों की भरमार है। नैनो टेक्नोलॉजी वैज्ञानिकों को व्यावहारिक सीमाओं से परे जाकर आणविक स्तर पर प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करती है।

हर क्षेत्र में पैठ

नैनो टेक्नोलॉजी वर्तमान में मानवीय जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर चुकी है। यह तकनीक बायोसाइंस, मेडिकल साइंस, पर्यावरण विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, सिक्योरिटी, फैब्रिक्स और विविध क्षेत्रों में चमत्कार कर रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि नैनो टेक्नोलॉजी प्रत्येक क्षेत्र जैसे मेडिसिन, एयरोस्पेस, इंजीनियरिंग, विभिन्न उद्योगों और तकनीकी क्षेत्रों, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। कुल मिलाकर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा, जो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगा।

आर एंड डी पर आधारित

आने वाले समय में नैनो टेक्नोलॉजी के फायदों को देखते हुए पूरे विश्व में अकादमिक स्तर पर इसे एक विषय के रूप में अपनाया जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हमारे देश में उपलब्ध हैं। एमटेक और एमएससी कोर्स में प्रवेश के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोइंफॉर्मेटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन आदि विषयों से ग्रेजुएशन कर चुके विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। एडमिशन प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाता है।

नैनो टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम का स्वरूप मूलत : रिसर्च एवं डेवलपमेंट (आर एंड डी) पर आधारित होता है। इसके पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को पहले संबंधति विषय के आधारभूत सिद्धांतों से परिचित कराया जाता है। इसके बाद इस तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के अनुरूप अप्लाइड रूप देकर अन्य विषयों की जानकारी दी जाती है, ताकि पाठ्यक्रम रोचक, वस्तुनिष्ठ व ज्ञान पर आधारित बन सके। इसमें पदार्थ के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों का सूक्ष्मतम अध्ययन कराया जाता है। पाठ्यक्रम की विषयवस्तु में क्वांटम थ्योरी, लिथोग्राफी, कार्बनिक और अकार्बनिक नैनो मटेरियल, स्पेक्ट्रोग्राफी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, एक्स-रे डिफ्रैक्शन, रमन प्रभाव, नैनो बायोसाइंस, जीन स्ट्रक्चर आदि शामिल हैं।

करियर के कई विकल्प

नैनो टेक्नोलॉजी का अध्ययन करने वालों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में करियर के अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। यह तकनीक रक्षा, सैन्य सामग्री निर्माण, फॉरेंसिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करती है। नैनो टेक्नोलॉजी पर्यावरण, कृषि, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार प्रदान करती है। इस तकनीक का प्रयोग कैंसर के इलाज में भी किया जा रहा है। इसलिए स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में यह तकनीक अच्छी करियर की संभावनाएं रखती है। नैनो टेक्नोलॉजी के अध्यापन के क्षेत्र में भी करियर बनाया जा सकता है।

खुल रहे हैं नए द्वार

नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा विभिन्न तत्वों की बॉण्ड संरचना में परिवर्तन करने पर या उनका आपस में संयोग करने पर एकदम नए तत्व का निर्माण भी किया जा सकता है। इस विषय में अभी बहुत-से नए आयाम खोजे जाने बाकी हैं तथा इसके प्रयोग से भौतिकी के लगभग सभी सिद्धांतों को यथार्थ रूप दे पाना संभव हो सकता है। इसलिए यह विषय शोधर्थियों के लिए कार्यक्षेत्रों के नए द्वार खोलता है। इस टेक्नोलॉजी को और भी उन्नात बनाने तथा भविष्य में इस क्षेत्र में नई संभावनाओं की तलाश करने के लिए भारत सरकार भी पहल कर रही है। अमेरिका का नेशनल साइंस फाउंडेशन 'नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव' नामक योजना चला रहा है। इसके साथ ही विश्व के तमाम उन्नत देश भी इस पर अलग-अलग नामों से योजनाएं चला रहे हैं। अनेक देश इस विषय में शोध के लिए प्रतिवर्ष अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। स्पष्ट है कि इसके चलते इस क्षेत्र में जॉब्स के भरपूर अवसर निर्मित होने जा रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी को आज जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वे हैं शिक्षित, प्रशिक्षित तथा कुशल कर्मचारियों की कमी। नैनो टेक्नोलॉजी विभिन्न प्रमुख नवाचारों के विकास में संलग्न है और इस क्षेत्र में नित नए प्रयोग हो रहे हैं, जिससे कुशल मानवशक्ति को रोजगार के उजले अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

प्रमुख संस्थान

- आईआईटी, दिल्ली
- आईआईटी, गुवाहाटी
- आईआईटी, कानपुर
- जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरू
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरू
- नेशनल केमिकल लैबोरेट्री, पुणे
- एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा
- दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

स्वामी, प्रकाशक एवं मुंद्रक – नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड़, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-बी, फेस- 2, इंडस्ट्रियल इस्टेट, गंग्याल जम्मू से मुद्रित। संपादक– नीलम सिंह गिल। फोन नंबर : (95) 191-2574109, 2548103 RNI Regd. No: JKBIL/2004/13144 Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com

विधि विभाग ने जम्मू-कश्मीर में कानूनी पहुँच बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह की पहली 'नागरिक केंद्रित सेवाएँ' पहल की शुरूआत की

श्रीनगर 01 अगस्त। नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, विधि, न्याय एवं संसदीय कार्य विभाग ने मुख्य सचिव अटल डुल्लू के समक्ष 'नागरिक केंद्रित सेवाएँ' नामक एक नई पहल प्रस्तुत की। विधि सचिव अचल सेठी के नेतृत्व में, सूचना प्रौद्योगिकी सचिव डॉ. पीयूष सिंगला, राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी, जेएस मोदी और अन्य की उपस्थिति में, जनता को व्यापक कानूनी और प्रशासनिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन और हेल्पलाइन का लाभ उठाने की एक व्यापक योजना का विवरण दिया गया।

इस पहल को दस अलग-अलग मॉड्यूल में संरचित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक को कानूनी सहायता/सलाह मॉड्यूल सहित प्रमुख सेवाओं तक जनता की पहुँच को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मॉड्यूल नागरिकों को मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन के माध्यम से कानूनी सहायता और सलाह लेने में मदद करेगा। यह मॉड्यूल उन्हें कानूनी सहायता परामर्शदाताओं और निःशुल्क परामर्शदाताओं से जोड़ेगा और राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के संपर्क विवरण प्रदान करेगा।

यह मोबाइल एप्लिकेशन केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिनियमों, नियमों और अधिसूचनाओं तक आसान पहुँच प्रदान करेगा, साथ ही विधि विभाग की वेबसाइट और भारत संहिता वेबसाइट के लिंक भी प्रदान करेगा। इसमें अधिवक्ताओं से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं और अधिवक्ताओं के लिए करियर मार्गदर्शन प्रदान करने की अनूठी विशेषता होगी। ऐप नागरिकों को विभिन्न कानूनों के तहत दस्तावेजों के पंजीकरण और विवाह पंजीकरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु अनूठी सुविधाएँ भी प्रदान करेगा। यह मॉड्यूल विधायकों की सूची, उनके संपर्क विवरण, विधायी कार्य, समिति की रिपोर्ट और विधान सभा में प्रश्नोत्तर प्रदान करेगा। यह लाइव कार्यवाही के लिए एक लिंक और मसौदा विधेयक पर जनता की राय जानने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। मोबाइल ऐप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों सहित विभिन्न न्यायालयों की जानकारी, वाद सूची और मुकदमों की स्थिति भी शामिल होगी। यह ऐतिहासिक निर्णयों और न्यायालयों व उनके स्थानों के विवरण के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। यह मॉड्यूल नागरिकों को कानून से संबंधित शिक्षा के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ-साथ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और विधि पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले स्थानीय विश्वविद्यालयों की सूची भी प्रदान करता है। आवेदन कैसे और कब करें, इस बारे में कानूनी विशेषज्ञों की सलाह भी प्रदान करेगा। इस खंड में अधिवक्ताओं के लिए नामांकन प्रक्रिया, कल्याणकारी योजनाओं, नोटरी और शपथ आयुक्त सेवाओं, और सरकारी अधिवक्ताओं व स्थायी परामर्शदाताओं की सूची का विवरण शामिल होगा। नागरिक पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कार्यालयों का स्थान, मॉडल टेम्पलेट, आवश्यक दस्तावेजों की एक चेकलिस्ट और स्टाम्प विक्रेताओं की सूची शामिल है।

राणा ने मनकोट के जमीनी स्तर पर बदलाव और नीति आयोग के एबीपी के तहत राष्ट्रीय मान्यता की सराहना की

पुंछ 01 अगस्त। जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने पुंछ जिला प्रशासन और पंचायती राज संस्थाओं सहित स्थानीय समुदाय की मनकोट ब्लॉक में उल्लेखनीय विकास कार्यों में उनके सामूहिक प्रयासों के लिए सराहना की। मनकोट ब्लॉक को नीति आयोग के प्रमुख आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है।

पुंछ के डाक बंगले में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए, राणा ने मनकोट ब्लॉक की परिवर्तनकारी उपलब्धियों का जश्न मनाया, जो उन्होंने कहा कि सफल जमीनी स्तर के शासन और समुदाय-संचालित विकास का एक अग्रणी उदाहरण बनकर उभरा है।

मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एक दूरस्थ, उपेक्षित ब्लॉक से देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ब्लॉकों में से एक के रूप में मनकोट का उदय, केंद्रित कार्यान्वयन, उत्तरदायी प्रशासन और स्थानीय भागीदारी की शक्ति का प्रतीक है।

मंत्री ने कहा, मनकोट की यात्रा न केवल प्रभावशाली रैंकिंग की कहानी है, बल्कि यह दृढ़ संकल्प और विश्वास की भी कहानी है। यह हमारे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की

प्रतिबद्धता, विभागों के बीच तालमेल और लोगों के इस विश्वास को दर्शाती है कि विकास समावेशी, समतामूलक और दूरगामी होना चाहिए।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 90 दिनों के केंद्रित संतृप्ति अभियान के दौरान परिवर्तन में उल्लेखनीय तेज़ी आई, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और वित्तीय समावेशन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रमुख विकास लक्ष्य हासिल करना था। इस अभियान में उच्च-स्तरीय अंतर-विभागीय समन्वय और मज़बूत सामुदायिक सहभागिता देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप ज़मीनी स्तर पर उल्लेखनीय सुधार हुए। राणा ने गर्व के साथ कहा कि मनकोट ब्लॉक ने देश भर के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 9वां स्थान और जम्मू संभाग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसे पुंछ के विकास पथ में एक मील का पत्थर कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, यह अंत नहीं, बल्कि एक नए मिशन की शुरुआत है।

राणा ने पुंछ में आकांक्षा हाट का शुभारंभ किया

पुंछ 01 अगस्त। जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री, जावेद अहमद राणा ने आकांक्षा हाट का उद्घाटन किया, जो ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने और पूरे क्षेत्र में जमीनी स्तर के समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है।

इस शुभारंभ समारोह में स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय कारीगरों, सरकारी अधिकारियों और आम जनता की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जो समावेशी और सतत ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्थापित, आकांक्षा हाट की संकल्पना स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण कारीगरों के लिए अपने उत्पादों के प्रदर्शन, प्रचार और विक्रय हेतु एक समर्पित मंच के रूप में की गई है।

इस पहल का मूल उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और सीमावर्ती एवं आदिवासी क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है।

उद्घाटन समारोह के दौरान, मंत्री ने हस्तनिर्मित वस्त्रों, पर्यावरण-अनुकूल शिल्पकला, जैविक उत्पादों और प्रसंस्.त स्थानीय खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित करने वाले विविध प्रकार के स्टॉलों का अवलोकन किया।

राणा ने प्रदर्शनियों में प्रदर्शित रचनात्मकता, शिल्प कौशल और सांस्.तिक समृद्धि की सराहना की और क्षेत्रीय परंपराओं के संरक्षण के प्रति कलाकारों के समर्पण की सराहना की।

जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास के लिए उमर के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, मंत्री महोदय ने ग्रामीण उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों के लिए स्थायी बाजार संपर्क बनाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवारों में दीर्घकालिक आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने कहा कि आकांक्षा हाट की परिकल्पना केवल एक भौतिक बाज़ार के रूप में नहीं, बल्कि एक गतिशील और स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में की गई है जो ग्रामीण उत्पादकों को उपभोक्ताओं और संस्थागत खरीदारों से सीधे जोड़ता है।

एक स्थायी विपणन मंच प्रदान करके, सरकार का उद्देश्य बिचौलियों पर निर्भरता कम करना, आय के स्रोतों का विस्तार करना और जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

उपराज्यपाल ने उच्च कमान पाठ्यक्रम-54 के अधिकारियों से बातचीत की

श्रीनगर 01 अगस्त। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आर्मी वॉर कॉलेज महू में उच्च कमान पाठ्यक्रम-54 में भाग लेने वाले अधिकारियों से बातचीत की। उपराज्यपाल ने राजभवन में आर्मी वॉर कॉलेज के अधिकारियों और संकाय सदस्यों को संबोधित किया और समकालीन भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक मुद्दों के साथ-साथ आतंकवाद-रोधी रणनीति और आतंकवादी तंत्र को खत्म करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण पर चर्चा की। उपराज्यपाल ने कहा, मैं तीनों सेनाओं के उत्कृष्ट अधिकारियों को सभी नागरिकों की सुरक्षा और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूँ। हमें अपनी सुरक्षा, संरक्षा और समृद्धि के लिए खतरा बनने वाले हर आतंकवादी और आतंकवादी संगठन को खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए।

मुख्य सचिव ने जन शिकायत निवारण तंत्र और पीएसजीए के कार्यान्वयन की समीक्षा की

श्रीनगर 01 अगस्त। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने यहाँ 'जेके समाधान' और सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं के समाधान में लोक शिकायत विभाग की कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक बैठक आयोजित की।

इस बैठक में विभाग के सभी प्रशासनिक सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्र शासित प्रदेश के सभी उपायुक्तों ने इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने जेके समाधान पोर्टल पर चल रहे उन्नयन की बारीकी से जाँच की, जिसका उद्देश्य इसे अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और शिकायत निवारण में कुशल बनाना है। शिकायत निपटान समय-सीमा और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक विस्तृत जिला-वार और विभाग-वार निष्पादन लेखा परीक्षा की गई। जन संपर्क के महत्व पर ज़ोर देते हुए, मुख्य सचिव ने इस प्रणाली में जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लगभग 21 लाख परिवारों के साथ, नागरिक पंजीकरण को लगभग 20 लाख तक ले जाने की गुंजाइश है।

उन्होंने डीओपीजी को पोर्टल के डैशबोर्ड को और अधिक व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक बनाने का निर्देश दिया, ताकि वास्तविक समय में शिकायतों का प्रवाह, प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर प्रतिक्रिया समय और शिकायतों के समाधान पर नागरिकों की प्रतिक्रिया को प्रतिबिंबित किया जा सके। उन्होंने लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों को सूचित करने के लिए भूगोल, जनसांख्यिकी और समुदाय के अनुसार शिकायतों के पैटर्न को उजागर करने वाले विश्लेषण की आवश्यकता पर भी बल दिया।

प्रशासनिक सचिव और उपायुक्त इस प्रणाली को और अधिक प्रभावी और सुगम बनाने के लिए सुझाव देने के लिए सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया। मुख्य सचिव ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को निर्देश दिया कि वे आगामी समीक्षा से पहले पोर्टल के अगले संस्करण में ऐसी सभी जानकारियों को शामिल करें।

डीओपीजी के सचिव, नीरज कुमार ने बैठक में बताया कि जेके समाधान पर 13,73,252 नागरिकों ने पंजीकरण कराया है और 77,810 शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिनमें से 62,370 का समाधान किया जा चुका है।

सीपीजीआरएएमएस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर दर्ज 9,022 शिकायतों में से 5,628 का समाधान हो चुका है और 3,394 पर अभी कार्रवाई चल रही है।

बाद में, जम्मू-कश्मीर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक अलग बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्य सचिव ने अधिनियम के तहत प्रस्तुत सेवा अनुरोधों के समय-श्रृंखला डेटा की निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल बनाने का आह्वान किया।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पोर्टल को अधिकारियों द्वारा आवेदनों के प्रसंस्करण में लगने वाले समय की विस्तृत जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जिससे प्रशासन आदतन देरी की पहचान कर सके और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित कर सके।

उपायुक्त ने श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा तीर्थयात्रियों के जत्थे का स्वागत किया

पुंछ 01 अगस्त। पुंछ उपायुक्त विकास कुंडल ने श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा तीर्थयात्रियों के 5वें जत्थे का स्वागत करने के लिए कॉलेज ग्राउंड स्थित यात्रा बेस कैंप का दौरा किया।

उनके साथ अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, सहायक आयुक्त राजस्व, एसीडी, तहसीलदार हवेली, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस दौरान, उपायुक्त ने विभिन्न विभागीय स्टालों का निरीक्षण किया, तीर्थयात्रियों को प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की, लंगर सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन किया और सुचारू एवं सुरक्षित तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा एवं आवास व्यवस्था का जायजा लिया।

उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, उपायुक्त ने यात्रा के सफल और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने तीर्थयात्रियों का हार्दिक स्वागत किया और उनसे हर वर्ष पवित्र तीर्थस्थल पर आते रहने का आग्रह किया।

किश्तवाड़ हर घर तिरंगा अभियान-2025 के लिए तैयार

किश्तवाड़ 01 अगस्त। किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा ने आगामी 2 अगस्त से 15 अगस्त, 2025 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान 2025 की तैयारियों का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

यह अभियान तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा यानी 2 अगस्त से 8 अगस्त, 9 अगस्त से 12 अगस्त और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक। शुरुआत में, अतिरिक्त उपायुक्त पवन कोतवाल ने तीनों चरणों में नियोजित गतिविधियों की विस्तृत जानकारी साझा की। जिले भर में विभिन्न स्थानों पर रंगोली प्रतियोगिताएं, तिरंगा राखी बनाने की कार्यशालाएं और तिरंगा बाइक रैलियां जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं।

हर घर तिरंगा अभियान के साथ, एक सप्ताह तक चलने वाला स्वच्छता अभियान भी शुरू किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि ज़िले की सभी पंचायतों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और ऐतिहासिक चौगान मैदान में एक विशेष महासफ़ाई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

इस अभियान को एक राष्ट्रीय अभियान बताते हुए, उपायुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों को इसमें अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने समावेशी समारोहों के महत्व पर भी ज़ोर दिया और सभी से एकता और देशभक्ति की भावना के साथ इस अभियान में भाग लेने का आग्रह किया।

इसके अलावा, उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को अभियान के दौरान ध्वजारोहण समारोह आयोजित करने और सरकारी भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों, पुलों, होटलों और प्रमुख सार्वजनिक बुनियादी ढाँचों को रोशन करने का निर्देश दिया।

एएसपी ने बैठक में अभियान के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए किए गए सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी दी।

उपायुक्त ने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपने-अपने कार्यालयों में तिरंगा फहराने और आम जनता को भी अपने घरों और स्कूलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा।

उन्होंने सभी से इस अभियान को पूरे जोश, उत्साह और राष्ट्रीय भावना के साथ मनाने का आग्रह किया।

उपायुक्त ने हर घर तिरंगा अभियान के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य, पीएचई, पीडीडी, स्वच्छता आदि आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं से संबंधित व्यवस्थाओं की भी विस्तृत समीक्षा की।

उपायुक्त ने उधमपुर में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों पर चर्चा की

उधमपुर 01 अगस्त। उपायुक्त उधमपुर सलोनी राय ने जिले में हर घर तिरंगा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारियों पर चर्चा के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई।

बैठक में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजिंदर सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त प्रेम सिंह, पीओ पोषण सुभाष डोगरा, जीएम डीआईसी किशोर सिंह कटोच, सहायक आयुक्त राजस्व डॉ. उमेश शान, मुख्य योजना अधिकारी उत्तम सिंह और संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में उपायुक्त ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में स्वतंत्रता और देशभक्ति की भावना को समर्पित गतिविधियों, कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि हर घर तिरंगा पहल का उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति की गहरी भावना जगाना, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

उपायुक्त ने सभी विभागों को अभियान के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियाँ पहले से ही पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने पहले ही आवश्यक व्यवस्थाएँ कर ली हैं और सभी हितधारकों से निर्धारित कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निकट समन्वय से काम करने का आग्रह किया।

UNION TERRITORY OF JAMMU & KASHMIR
OFFICE THE EXECUTIVE ENGINEER PWD (R&B) DIVISION GANDHI NAGAR JAMMU
LOK NIRMAN BHAWAN RAIL HEAD COMPLEX JAMMU
e-mail : xenpwddivgandhinagar@gmail.com

EXTENSION NOTICE

Name of work :- Notice Inviting Tender for Providing and laying of Wire Crates in Alam Dhar Colony Sunjwan Jammu (Under M.H3054 Non Plan) (1.35 Lacs)
Reference :- This office Short e-NIT No. DGN/42 of 2025-26 dated 24-07-2025 (S.No. 3).
Due to poor response, the date of downloading, submission of bid and opening of Technical bid figuring at S.No. 3 is hereby extended as per below :-

Sl. No. of Bidding Document	Read as	Instead of
Page No. 1 & 2 of e-NIT	Period of downloading of bidding documents **From 24-07-2025 to 04-08-2025, 1800 Hrs**	Period of downloading of bidding documents **From 24-07-2025 to 30-07-2025, 1800 Hrs**
	Bid Submission End Date **05-08-2025 upto 1800 Hrs**	Bid Submission End Date **30-07-2025 upto 1800 Hrs**
	Date & time of opening of Technical Bids (Online) **05-08-2025 on or after 1200 Hrs in the Office of Executive Engineer PWD (R&B) Division Gandhi Nagar Jammu**	Date & time of opening of Technical Bids (Online) **31-07-2025 on or after 1200 Hrs in the Office of Executive Engineer PWD (R&B) Division Gandhi Nagar Jammu**

All other terms and conditions shall remain same.
No :- 8682-93
Dated :- 31-07-202

. Sd ..
(Er. Rahat Gupta)
Executive Engineer
PWD (R&B) Division
Gandhi Nagar

DIP/J-4172/25
Dtd: 1-8-2025

JKSSB-PSC की लापरवाही से बढ़ रही बेरोजगारी : सुनील डिम्पल

जम्मू, 1 अगस्त। मिशन स्टेटहुड जम्मू-कश्मीर के अध्यक्ष सुनील डिम्पल ने सरकार से मांग की कि वह नायब तहसीलदारों की भर्ती प्रक्रिया को तुरंत शुरू करे और सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरे। उन्होंने आरोप लगाया कि छ्व्यस्स्क और क्र्स्ट ने नायब तहसीलदारों की भर्ती प्रक्रिया रोक दी है, जिससे युवाओं में भारी निराशा है।

डिम्पल ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मांग की कि वे नायब तहसीलदारों की भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू करें, अन्यथा सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 8300 खाली पदों को भरने की दिशा में तुरंत कदम उठाने चाहिए। डिम्पल ने यह भी आरोप लगाया कि सब-इंस्पेक्टर (SI) की भर्ती प्रक्रिया को भी रोक दिया गया है, जिससे योग्य युवाओं को नुकसान हो रहा है। उन्होंने मांग की कि सीजनल टीचर्स को नियमित किया जाए, उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए और उन्हें स्थायी नियुक्ति दी जाए।

इसके अलावा उन्होंने वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स, किसान खिदमत घर, SPOs, रेहबर-ए-खेल, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, जंगलात विभाग, रेहबर-ए-तालीम, स्वास्थ्य कर्मियों, नेशनल यूथ कोर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, प्रधानमंत्री आयुष्मान गोल्ड कार्ड मित्रों, स्ट्राइक पर चल रहे डेली वेजर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, SRO-43 के अंतर्गत आने वाले कर्मियों, CPW और भूमि दाताओं को भी नियमित करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार को स्टाइपेंड की व्यवस्था करनी चाहिए और दैनिक वेतनभोगियों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। डिम्पल ने आरोप लगाया कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक वेतनभोगियों को 29,000 से 45,000 तक वेतन दिया जा रहा है, जबकि जम्मू-कश्मीर के युवाओं के साथ यह भेदभाव है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय जम्मू-कश्मीर के साथ अन्याय कर रहा है और यह भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। डिम्पल ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आग्रह किया कि वे अपने वादे को निभाएं और जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनः गठन करें। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, जिससे बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। उनके अनुसार, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में सभी रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं। डिम्पल ने कहा कि विधानसभा चुनावों के बाद जनता की उम्मीदों पर पानी फिर गया है और अब केवल राज्य की बहाली ही एकमात्र समाधान है जिससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके।

संपादकीय

अमेरिका भारत के साथ कड़े टैरिफ़ के रास्ते पर चल रहा

अमेरिकी सरकार के नज़रिए से भारत स्पष्ट रूप से कठघरे में है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत से आयातित सभी वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा, पश्चिमी शक्ति ने रूस से सैन्य उपकरण और कच्चा तेल खरीदने पर अतिरिक्त जुर्माना (अनिर्दिष्ट) लगाया है। इस घटनाक्रम ने भारत को एक अनिश्चित स्थिति में डाल दिया है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए इस कदम से देश के आर्थिक हितों को नुकसान पहुँचने की संभावना है। हालाँकि इस कदम के परिणामों के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित रूप से 1 अगस्त के बदलावों के बाद दोनों देशों के बीच मधुर संबंध पहले जैसे नहीं रहेंगे। इसके अलावा, अब भारत को अपनी विदेश नीति के ढाँचे को नए सिरे से समायोजित करने की आवश्यकता है, अन्यथा चीजें गड़बड़ा सकती हैं क्योंकि अमेरिका का कड़ा रुख देश के पक्ष में नहीं दिख रहा है। भारत के लिए अमेरिका के साथ संबंधों पर पुनर्विचार करने और आर्थिक रूप से मज़बूत बनने की सभी संभावनाओं को तलाशने का समय आ गया है, क्योंकि किसी देश या देशों के समूह का आँख मूँदकर अनुसरण करना भारत के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि यह दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और हितों की रक्षा करना उसका वाजिब अधिकार है। कथित तौर पर, अमेरिका की यह घोषणा आश्चर्यजनक रही है, क्योंकि दोनों देश एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे थे। चूँकि आयात शुल्क आयात करने वाले देश में वस्तुओं को महंगा बनाता है, इसलिए यह आशंका है कि नए टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका में भारतीय वस्तुओं की माँग कम हो जाएगी, जिससे घरेलू उत्पादकता में कमी आएगी, जिसका असर रोज़गार पर पड़ सकता है, जो भारत के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण है। कथित तौर पर, इस कदम से भारतीय श्रम-प्रधान वस्तुएँ जैसे वस्त्र, चमड़ा और गैर-चमड़ा जूते, रत्न एवं आभूषण, कालीन और हस्तशिल्प प्रभावित हो सकते हैं, जो देश के लिए अच्छी खबर नहीं है, जो पहले से ही पिछले कई वर्षों से बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत एक बड़ा राष्ट्र है और उसके पास बहुत सारे अवसर हैं, इसलिए उसे इस घटनाक्रम से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार को कूटनीतिक माध्यमों से इसका समाधान ढूंढना चाहिए तथा अन्य देशों के साथ संभावनाएं तलाशनी चाहिए, क्योंकि इसे अंत नहीं माना जाना चाहिए।

पीएम-किसान- किसानों के सशक्तिकरणऔर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के रूपांतरण का भारत का वैश्विक खाका

पीएम-किसान की सफलता का श्रेय भारत के मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे को जाता है। जेएएम की तिकड़ी -जन धन बैंक खाते, आधार बायोमेट्रिक पहचान और मोबाइल कनेक्टिविटी - ने बड़े पैमाने पर लाभ के निर्बाध वितरण को संभव बनाया है। स्व-पंजीकरण से लेकर भूमि स्वामित्व के सत्यापन और डीबीटी द्वारा समर्थ भुगतान तक, इस पूरी योजना का जीवनचक्र डिजिटल है।राज्य सरकारों के सहयोग से, पीएम-किसान डिजिटल रूप से समन्वित तथा एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से पहुंचने वाले शासन के एक बेहतरीन मॉडल के रूप में कार्य करता है। इसने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों, लाभार्थियों के डेटाबेस और भुगतान प्रणालियों को सफलतापूर्वक समन्वित किया है औरइससे दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में किसान-केन्द्रित एक उत्तम संरचना का निर्माण हुआ है।

पीएम किसान ने कृषि से जुड़े इकोसिस्टम में किसान ई-मित्र वॉयस-आधारित चैटबॉट और एग्री स्टैक जैसी नवीन परियोजनाओं को भी प्रेरित किया है। एग्रीस्टैक व्यक्तिगत, समय पर और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है, जिससे भारतीय कृषि भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार हो सके।

- डॉ. प्रमोद मेहरदा, अतिरिक्त सचिव एवं अरिंदम मोदक, सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

समावेशी विकास और ग्रामीण समृद्धि के सफर में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना, भारत सरकार की एक अग्रणी पहल के रूप में उभर कर सामने आई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई, इस पहल ने लाखों छोटे एवं सीमांत किसानों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है और पूरी तरह से डिजिटल, कुशल एवं पारदर्शी प्रणाली के जरिए प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने के एक वैश्विक मॉडल के रूप में खुद को स्थापित किया है।

प्रत्यक्ष समर्थन के जरिए किसानों का सशक्तिकरण

मूल रूप से,पीएम-किसान योजना पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है। यह सहायताराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के जरिए 2,000 रुपये की तीन बराबरकिस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। इस सुव्यवस्थित एवंतकनीक-संचालित कदम से बिचौलियों की भूमिका, लाभ मिलने में होने वाली देरी और त्रुटि की गुंजाइशखत्म होतीहै और एक-एक पाई इच्छित लाभार्थी तक पहुंचना सुनिश्चित होता है।

इस योजना की शुरुआत से लेकर अब-तक,कुल 3.69 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को हस्तांतरित की जा चुकी है। इस प्रकार, पीएम-किसान दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल रूप से क्रियान्वित नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों में से एक बन गया है। आंकड़ों से परे, यह कदम सब्सिडी से हटकर सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ने संबंधीएक बदलाव का प्रतीक है।बातचाहे बीज की हो या उपकरण या शिक्षा या फिर स्वास्थ्य की, इस योजना से किसानों को यह तय करने की आजादी मिलती है कि वे इस सहायता का सबसे बेहतरइस्तेमाल कैसे करें।

भारत के छोटे किसानों के हित में एक परिवर्तनकारी कदम

दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले भारत के 85प्रतिशत से अधिक किसानों के लिए ये लाभ बुवाई या कटाई के मौसम में एक अहम आर्थिक सेतु का काम करते हैं। ये लाभ अल्पकालिक नकदी प्रवाह के तनाव को कम करते हैं, अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता में कमीलाते हैंऔर संकट के समय एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं।

वित्तीय सहायता से कहीं बढ़कर, पीएम-किसान योजना समावेशिता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक भागीदार के रूप में किसान की मान्यता का प्रतीक है।

डिजिटल शासन की श्रेष्ठता

पीएम-किसान की सफलता का श्रेय भारत के मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे को जाता है। जेएएम की तिकड़ी -जन धन बैंक खाते, आधार बायोमेट्रिक पहचान और मोबाइल कनेक्टिविटी - ने बड़े पैमाने पर लाभ के निर्बाध वितरण को संभव बनाया है। स्व-पंजीकरण से लेकर भूमि स्वामित्व के सत्यापन और डीबीटी द्वारा समर्थ भुगतान तक, इस पूरी योजना का जीवनचक्र डिजिटल है।

राज्य सरकारों के सहयोग से, पीएम-किसान डिजिटल रूप से समन्वित तथा एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से पहुंचने वाले शासन के एक बेहतरीन मॉडल के रूप में कार्य करता है। इसने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों, लाभार्थियों के डेटाबेस और भुगतान प्रणालियों को सफलतापूर्वक समन्वित किया है औरइससे दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में किसान-केन्द्रित एक उत्तम संरचना का निर्माण हुआ है।

पीएम किसान ने कृषि से जुड़े इकोसिस्टम में किसान ई-मित्र वॉयस-आधारित चैटबॉट और एग्री स्टैक जैसी नवीन परियोजनाओं को भी प्रेरित किया है। एग्रीस्टैक व्यक्तिगत, समय पर और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है, जिससे भारतीय कृषि भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार हो सके।

वैश्विक मानकों की स्थापना

दुनिया भर में, प्रत्यक्ष लाभ कार्यक्रमों को गरीबी उन्मूलन के कारगर साधनों के रूप में तेजी से मान्यता मिल रही है। फिर भी, पीएम-किसान की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं —इसका विशाल आकार, गति और डिजिटल विश्वसनीयता इसे बिखरी हुई कृषि सहायता प्रणालियों में सुधार के लिए प्रयासरत देशों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बनाती है।

आईएफपीआरआई, एफएओ, आईसीएआर और आईसीआरआईएसएटीजैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने छोटे किसानों की आय बढ़ाने, ऋण की सुलभता में सुधार, असमानता को कम करने और आधुनिक कार्यप्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में पीएम किसान की भूमिका पर प्रकाश डाला है। कई देशों में जारी सशर्त हस्तांतरण के उलट, इसका विश्वास-आधारित वबिना शर्त वाला दृष्टिकोण, सहभागी एवंसम्मान-आधारित कल्याणकारी वितरण की दिशा में एक बड़ी छलांग है।

ग्रामीण विकास को गति देना

पीएम-किसान का सकारात्मक प्रभाव केवल व्यक्तिगत लाभार्थियों तक ही सीमित नहीं है। इसके तहत होने वाले अनुमानित नकदी प्रवाह ने ग्रामीण बाजारों को पुनर्जीवित किया है, कृषि-उत्पादों की मांग को प्रोत्साहित किया है और घरेलू उपभोग के पैटर्न को मजबूत किया है। इसने महिलाओं को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर उन मामलों में जहांबैंक खाते संयुक्त रूप से खोले जाते हैं।

इसके अलावा, यह एक समग्र और परस्पर संबद्ध ग्रामीण विकास इकोसिस्टम का निर्माण करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम फसल बीमा योजना और ई-नाम जैसी अन्य प्रमुख योजनाओं का पूरक है। किसानों के लिए एक पेंशन योजना, पीएम-किसान मानधन योजना के साथ इसका एकीकरण, भारत के कृषि कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

सुनहरे भविष्य का एक दृष्टिकोण- दृढ़ता, समानता और स्थिरता

पीएम-किसान एक वित्तीय सहायता तंत्र से कहीं बढ़करहै। यह भारत सरकार के किसानों के नेतृत्व वाले विकास का एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। अधिकार से सशक्तिकरण की ओर, सहायता से स्वायत्तता की ओर स्थानांतरित होकर, यह राज्य और किसान के बीच अनुबंध को नए सिरे से परिभाषित करता है।

भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है, ऐसे में पीएम-किसान जैसी पहल समावेशी प्रगति की नींव रखती है। उन्नत तकनीकों के निरंतर एकीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति दृढ़ता, स्थिरता और सटीक कृषि पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, यह योजना बदलाव की दिशा में एक बेहदशक्तिशाली कदमके रूप में विकसित होने के लिए तैयार है।

पीएम-किसान विश्वास, तकनीक और परिवर्तन की कहानी है। यह दुनिया के लिए भारत का योगदान है। यह योजना एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक दूरदर्शी नीति, डिजिटल नवाचार और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ मिलकर, लाखों लोगों को सशक्त बना सकती है और 21वीं सदी के शासन को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है।

प्रमोद मेहरदा अरिंदम मोदक

एआई का विस्तार या नौकरी का संकुचन एक बड़ी चुनौती

एआई और ऑटोमेशन केवल तकनीक नहीं हैं, वे कार्य संस्कृति, संगठन संरचना और मानव संसाधन नीति को मूल रूप से बदल रहे हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार, एआई से प्रेरित उत्पादकता और लागत में कटौती की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

भारत जैसे युवाओं वाले और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश में तकनीकी विकास के प्रति उत्साह हमेशा गहरा रहा है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप क्रांति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी तकनीकें समाज, राष्ट्र और अर्थव्यवस्था में तीव्र बदलाव की सारथि बनी हैं। हर वर्ग और क्षेत्र ने इस परिवर्तन को आशा एवं सकारात्मकता के साथ अपनाया है, इस उम्मीद में कि तकनीकी तरक्की के साथ रोज़गार के नए अवसर भी सृजित होंगे। लेकिन हाल ही में आईटी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) द्वारा 12,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया और इसे बड़ा झटका दिया है। निस्संदेह, छंटनी का यह फैसला आईटी क्षेत्र में आसन्न संकट की आहट को ही दर्शाता है। छंटनी बाबत टीसीएस की दलील है कि इन नौकरियों में कटौती कौशल की कमी और अपने विकसित होते व्यावसायिक मॉडल में कुछ कर्मचारियों को फिर से नियुक्त करने में असमर्थता के चलते की गई है। हालांकि, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का दावा है कि इस कदम के पीछे एआई से प्रेरित उत्पादकता वृद्धि नहीं है। यह संख्या कंपनी के कुल कार्यबल का लगभग 2 प्रतिशत है, और मुख्यत: मध्यम और वरिष्ठ स्तर के कर्मचारियों को प्रभावित करेगी।

एआई और ऑटोमेशन केवल तकनीक नहीं हैं, वे कार्य संस्कृति, संगठन संरचना और मानव संसाधन नीति को मूल रूप से बदल रहे हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार, एआई से प्रेरित उत्पादकता और लागत में कटौती की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर, एमेजोन ने 30,000 सॉफ्टवेयर एप्लिकेशनों को एआई की मदद से मात्र छह महीनों में अपग्रेड किया, जो कार्य सामान्यत: डेवलपर्स को एक वर्ष लगता। इससे कंपनी को लगभग 250 मिलियन डॉलर की बचत हुई। इसी प्रकार, माइक्रोसोफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों में कोडिंग का 20 से 50 प्रतिशत कार्य एआई से कराया जा रहा है। भारत में एआई का प्रसार अभी अमेरिका या यूरोप की तुलना में सीमित है, लेकिन इसकी गति तीव्र है। देश के स्टार्टअप और आईटी क्षेत्र में छंटनियों की संख्या बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार, केवल वर्ष 2025 के शुरुआती पांच महीनों में भारत में 3600 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया, जिसमें एआई आधारित लागत नियंत्रण एक प्रमुख कारण रहा। यह स्पष्ट करता है कि एआई के कारण दोहराव वाले कार्यों की उपयोगिता घट रही है और उनकी जगह स्मार्ट तकनीक ले रही है। मौजूदा समय में यह कदम लागत-अनुकूलन पहलों के चलते अन्य आईटी सेवा कंपनियों में भी छंटनी को बढ़ावा दे सकता है। इसमें दो राय नहीं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कारोबार के नियमों में मौलिक बदलाव के चलते, भविष्य के लिये तैयार रहना हर व्यावसायिक उद्यम के एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। इस नई हकीकत को देखते हुए, अनेक सवाल सबसे ज्यादा विचलित करने वाले बनकर उभर रहे हैं कि क्या यह तकनीकी बदलाव अनिवार्य रूप से कर्मचारियों की कीमत पर होना चाहिए? एआई युग में नौकरी की अनिश्चितता क्या तकनीक विकास के नाम पर विस्थापन नहीं है? छंटनी की चपेट में युवाओं का भविष्य क्या तकनीकी प्रगति के नाम पर मानव श्रम पर आघात नहीं है? क्या स्मार्ट मशीनें के दौर में भारत में रोजगार को नई चुनौती और इंसानों को हताशा में धकेलना नहीं है? एआई का विस्तार यानी नौकरी का संकुचन क्या भारत के लिए बड़ी चेतावनी की घड़ी बन रहा है?

इन प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में देश में बेरोजगारी का संकट किसी से छिपा नहीं है। देश में श्रमबल का

कौशल विकास धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है। सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में आईटी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। लेकिन टीसीएस के इस फैसले से आईटी पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे उन लाखों छात्रों और डिग्री लेकर निकल रहे उत्साही इंजीनियरों में निराशा व्याप्त होगी। भारत में बढ़ता रोजगार संकट केंद्र सरकार से निरंतर हस्तक्षेप की मांग करता है।

हाल ही में हरियाणा में हुई एक परीक्षा में लाखों युवाओं की भागीदारी इस बात का संकेत है कि रोजगार की मांग कितनी व्यापक और अवसर कितने सीमित हैं। देश ही नहीं, दुनिया में रोजगार का संकुचन एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। गोल्डमैन सोच्स की रिपोर्ट के अनुसार, एआई और ऑटोमेशन के चलते दुनिया भर में लगभग 300 मिलियन नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। विश्व आर्थिक मंच का आकलन है कि 2030 तक 92 मिलियन नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन उसी अवधि में 170 मिलियन नई नौकरियां भी पैदा होंगी। यह एक दोधारी तलवार है, जो बदलेगा, बचेगा; जो रुकेगा, वो हाशिए पर जाएगा।

टीसीएस का दावा है कि छंटनी का निर्णय भविष्य की जरूरतों के अनुसार संगठन को ढालने की रणनीति का हिस्सा है। कंपनी का ध्यान एआई में निवेश, नए बाजारों में प्रवेश, ग्राहक अनुभव सुधार और कार्यबल मॉडल के पुनर्गठन पर केंद्रित है। हालांकि, यह तर्क उन हजारों कर्मचारियों की व्यथा को शांत नहीं कर सकता जिनकी आजीविका पर इसका सीधा प्रहार हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से न केवल कंपनी के भीतर बल्कि समूचे आईटी क्षेत्र में आशंका, आक्रोश एवं अनिश्चितता का माहौल बन गया है। खासकर युवाओं और आईटी की पढ़ाई कर रहे लाखों छात्रों के लिए यह एक मानसिक झटका है। तकनीकी शिक्षा में दाखिले बढ़ रहे हैं, लेकिन रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं। यह असंतुलन देश की सामाजिक स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें बताती हैं कि विश्व स्तर पर लगभग 40 प्रतिशत नौकरियां एआइ से प्रभावित होने के कगार पर हैं, जिससे देश के मध्यवर्ग की आर्थिक स्थिरता को गहरा झटका लग सकता है।

टीसीएस की छंटनी ने बेरोजगारी के दौर में बड़ी हलचल मचाई है, हालांकि आईटी और तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिले बढ़े हैं, लेकिन उनमें व्यावहारिक और भविष्य-उन्मुख कौशल की कमी है। यह असंगति ही भविष्य में अधिक छंटनियों का कारण बन सकती है।

एआई हर भूमिका को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसे पुनर्परिभाषित करेगा। जहां दोहराव और विश्लेषण की आवश्यकता है, वहां एआई प्रभावी होगा, लेकिन रचनात्मकता, सहानुभूति और निर्णय क्षमता जैसे गुणों में मानव की भूमिका बनी रहेगी। डॉक्टर, शिक्षक, वकील, पत्रकार जैसे पेशों में एआईएक सहयोगी के रूप में कार्य करेगा, प्रतिस्थापन के रूप में नहीं। मेटा के प्रमुख एआई वैज्ञानिक यान लेकुन के अनुसार, 'एआई अधिकतर कार्यों का केवल एक हिस्सा ही कर सकता है, वह भी पूरी तरह परिपूर्ण नहीं। मानव श्रमिकों का सीधा प्रतिस्थापन संभव नहीं है।'

निश्चित तौर पर एआई और तकनीकी बदलाव अपरिहार्य हैं। सवाल यह है कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं? इसके लिए तीन प्रमुख कदम जरूरी हैं, पहला पुन:कौशल और सतत शिक्षा यानी कार्यबल को भविष्य के अनुरूप प्रशिक्षित करना होगा। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई एथिक्स, सॉफ्ट स्किल्स जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण अनिवार्य बनाना होगा। दूसरा नीतिगत समर्थन यानी सरकार को एआई नीति, डिजिटल समावेशन और श्रमिक सुरक्षा के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करने होंगे। रोजगार खोने वालों के लिए पुनर्वास योजनाएं और स्किल अपडेट कार्यक्रम आवश्यक हैं। तीसरा सांस्कृतिक और सामाजिक समायोजन यानी एआई को केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के रूप में भी देखा जाना चाहिए। इसे अपनाने में पारदर्शिता, विश्वास और सहयोग का वातावरण बनाना होगा। तकनीकी बदलाव नई संभावनाएं लेकर आते हैं, लेकिन वे अनायास ही चुनौतियां भी खड़ी करते हैं। टीसीएस की छंटनी से जो संदेश मिलता है वह यही है कि एआई युग में केवल वही टिकेगा जो परिवर्तनशील रहेगा। अब समय आ गया है कि हम तकनीक को केवल उपकरण नहीं, बल्कि नीति और जीवनशैली का हिस्सा मानें। सतत सीखना, अनुकूलन और सामाजिक न्याय, यही तीन स्तंभ हैं, जो भारत को इस तकनीकी क्रांति में न केवल जीवित, बल्कि अग्रणी बना सकते हैं।

ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

साभार : प्रभासाक्षी

किशन का इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन

प्रयागराज। शहर के युवा तेज गेंदबाज किशन कुमार का चयन ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में किया गया है। भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलियाई दौरा 21 सितम्बर से सात अक्टूबर तक चलेगा। आयुष महात्रे के नेतृत्व में 17 सदस्यीय टीम की घोषणा गुरुवार को हुई। इस टीम में आईपीएल के सनसनीखेज बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। नैनी स्थित डीपीएस मैदान पर चलने वाली आशीष नेहरा क्रिकेट अकादमी नैनी की प्रशिक्षक स्वाति सिंह ने बताया कि नैनी निवासी सुशील कुमार एवं रीना सिंह के पुत्र बायें हाथ के तेज गेंदबाज किशन कुमार ने अपने क्रिकेट कैरियर के प्रारम्भ से ही एएनसीए के प्रशिक्षु हैं। किशन अभी नोएडा में चल रहे इंडिया अंडर-19 टीम के हाई परफॉरमेंस कैंप में भाग ले रहे हैं। इससे पहले वह बेंगलूरू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के कैंप में भी शामिल थे। पिछले दो साल से किशन आईपीएल में गुजरात टाइटंस टीम के नेट गेंदबाज भी हैं। किशन के चयन पर दिल्ली पब्लिक स्कूल की अध्यक्ष सोनू सिंह, प्रधानाचार्या सुजाता सिंह, मुख्य प्रशिक्षक एनएस नेगी, स्वाति सिंह, यशवर्धन उचहारिया, मोहसिन अली, शिवराम पटेल आदि ने हर्ष व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी हैं।

पीकेएल सीज़न 12 की शुरुआत 29 अगस्त से, विशाखापत्तनम, जयपुर, चेन्नई और दिल्ली होंगे मेज़बान शहर

मुंबई। प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) सीज़न 12 की शुरुआत इस बार 29 अगस्त 2025 से होने जा रही है। चार शहरों विशाखापत्तनम (विजाग), जयपुर, चेन्नई और दिल्ली में फैले इस बहु-शहर प्रारूप में देशभर के दर्शकों को बेहतरीन कबड्डी एक्शन देखने को मिलेगा। ओपनिंग वीकेंड का शेड्यूल: पहला मुकाबला विजाग के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में तेलुगु टाइटंस और तमिल थलाइवाज के बीच खेला जाएगा। इसके बाद दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स का सामना पुनेरी पलटन से होगा। शनिवार, 30 अगस्त को तेलुगु टाइटंस एक बार फिर मैदान में उतरेंगे और इस बार उनका मुकाबला यूपी योद्धाज से होगा। वहीं, दूसरे मैच में यू मुंबा और गुजरात जायंट्स आमने-सामने होंगे। सुपर संडे के तहत तमिल थलाइवाज और यू मुंबा के बीच मुकाबला होगा, जिसके बाद गत चैंपियन हरियाणा स्टीलर्स अपनी खिताबी रक्षा की शुरुआत बंगाल वॉरियर्ज के खिलाफ करेंगे। विजाग की घर वापसी: पीकेएल सीज़न 12 के लिए विजाग की वापसी एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि यह शहर सात वर्षों बाद फिर से लीग की मेज़बानी कर रहा है। विजाग ने पहली, तीसरी और छठी सीज़न में भी पीकेएल की मेज़बानी की थी।

टोरंटो मास्टर्स: शेल्टन ने मानारिनो के खिलाफ हार का सिलसिला तोड़ा, रूबलेव की हार्डकोर्ट पर 250वीं जीत

टोरंटो। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी बेन शेल्टन ने टोरंटो मास्टर्स में फ्रांस के अनुभवी खिलाड़ी एड्रियन मानारिनो के खिलाफ पहली जीत दर्ज करते हुए तीसरे दौर में जगह बना ली। शेल्टन ने 56 मिनट में 6-2, 6-3 की आसान जीत हासिल की। इससे पहले दोनों आमने-सामने मुकाबलों में शेल्टन को हार का सामना करना पड़ा था।शेल्टन ने मैच के बाद कहा, यह जीत मेरे लिए बेहद अहम रही। वह शानदार शॉटमेकर हैं और कई बार वह आपके हाथ से रैकेट तक छीन लेते हैं। मैंने पहले भी उनके खिलाफ अच्छा खेला है लेकिन नतीजा मेरे पक्ष में नहीं रहा। पहले सेट में शेल्टन ने दो बार सर्विस ब्रेक कर बढ़त बनाई और दूसरे सेट में 5-3 की बढ़त हासिल कर ली। अंतिम गेम में उन्हें हल्की परेशानी हुई जब उन्होंने डबल फॉल्ट किया, लेकिन ब्रेक प्वाइंट बचाते हुए 16वें ऐस और एक शानदार सर्विस विनर के साथ मैच अपने नाम किया। शेल्टन ने कहा, मानारिनो के हाथ बहुत सधे हुए हैं। इसलिए सर्विस करते वक्त सटीकता बेहद जरूरी होती है। मैं खुश हूं कि मैंने आज अच्छा सर्व किया। वहीं, रूस के छठी वरीय एंड्री रूबलेव ने फ्रांस के ह्यूगो गैस्टन को 6-2, 6-3 से हराकर अपने करियर की हार्डकोर्ट पर 250वीं जीत दर्ज की।

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025: पूर्व 100 मीटर विश्व चैंपियन फ्रेड केरली प्रतियोगिता से बाहर

यूजीन (संयुक्त राज्य अमेरिका)। पूर्व 100 मीटर विश्व चैंपियन फ्रेड केरली ने इस सप्ताह ओरेगन में होने वाली यूएस ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप से नाम वापस ले लिया है, जिससे अब वह सितंबर में टोक्यो में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। 2022 में विश्व चैंपियन रह चुके और दो बार के ओलंपिक 100 मीटर पदक विजेता केरली ने सोशल मीडिया पर अपने नाम वापसी की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, 100 मीटर दौड़ एक सीधी स्प्रिंट होनी चाहिए। 2025 ने कई बाधाएं पेश की हैं। अब कुछ समय ट्रैक पर वापसी के लिए ले रहा हूं। इस साल कोई चैंपियनशिप नहीं। सभी समर्थकों का धन्यवाद। 30 वर्षीय केरली ने टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर में रजत पदक और 2024 पेरिस में कांस्य पदक जीता था।

खालिद जमील भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त

एजेंसी

नई दिल्ली। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने शुक्रवार को खालिद जमील को भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया, जिससे वह 2011-12 में सावियो मेडेइरा के बाद यह पद संभालने वाले पहले भारतीय बन गए। जमील ने मनोलो मार्केज़ का स्थान लिया है, जिन्होंने एक वर्ष से अधिक समय तक प्रतिस्पर्धी मैचों में जीत न मिलने के कारण पिछले महीने पद छोड़ दिया था। जमील का चयन तीन लोगों की शॉर्टलिस्ट में से किया गया था, जिनमें पूर्व राष्ट्रीय कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन और स्लोवाकिया के मैनेजर स्टीफन टारकोविक शामिल थे। एआईएफएफ की तकनीकी समिति ने राष्ट्रीय टीम के निदेशक सुब्रत पाल से परामर्श के बाद 22 जुलाई को इस सूची को अंतिम रूप दिया।

समिति ने एक ऐसे भारतीय कोच को प्राथमिकता दी जो टीम के सांस्कृतिक और विकासात्मक परिवेश से जुड़ सके, और यही वह कारक था जिसने जमील को इस सूची में शीर्ष पर पहुंचाया। एआईएफएफ कार्यकारी समिति ने 1 अगस्त को तकनीकी समिति की सिफ़ारिश का समर्थन किया और जमील की नियुक्ति की पुष्टि की।

बजट संबंधी चिंताओं ने भी इस निर्णय को प्रभावित किया। एआईएफएफ की आय 2023 में ?137.74 करोड़ से घटकर 2024 में ?110.5 करोड़ रह गई, और उसे इगोर स्टिमैक का अनुबंध समाप्त करने के लिए 400,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना पड़ा। इस बीच, मार्केज़ कथित तौर पर प्रति अंतरराष्ट्रीय विंडो 10,000 अमेरिकी डॉलर कमा रहे थे। ऐसे माहौल में एक अनुभवी भारतीय कोच को नियुक्त करना वित्तीय और फ़ुटबॉल दोनों ही दृष्टि से उचित था।

घरेलू ट्रैक रिकॉर्ड

49 वर्षीय इस जमील ने एक खिलाड़ी (2005 में महिंद्रा यूनाइटेड के साथ) और एक कोच (2017 में आइज़ॉल एफसी के साथ) के रूप में भारत के शीर्ष डिवीजन खिताब जीते हैं। एएफसी प्रो लाइसेंस धारक, जमील आई-लीग, आई-लीग 2 और इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) में कोचिंग कर चुके हैं। अंडरडॉग आइज़ॉल के साथ उनका आई-लीग खिताब जीतना, जो उसका पहला और एकमात्र शीर्ष-स्तरीय खिताब है, भारतीय फुटबॉल की सबसे यादगार उपलब्धियों में से एक है। हाल ही में उन्होंने 2023-24 सीज़न के मध्य में जमशेदपुर एफसी की कमान संभाली और टीम को सुपर कप सेमीफाइनल तक पहुँचाया, फिर उपविजेता और अगले आईएसएल सेमीफाइनल में पहुंचाया।

टोटनहैम ने एशिया टूर के दौरान आर्सेनल को हराया

एजेंसी

हांगकांग। हांगकांग के काई टैक स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए एक दोस्ताना मुकाबले में टोटनहैम हॉटस्पर ने आर्सेनल को 1-0 से मात दी। मैच में आर्सेनल ने मार्टिन ओडेगार्ड, बुकायो साका, काई हैवर्ट्ज़ और डेक्लन राइस जैसे स्टार खिलाड़ियों को मैदान में उतारा, वहीं टोटनहैम की ओर से क्रिस्टियन रोमेरो, मिकी वैन डी वेन और मोहम्मद कुदुस जैसे प्रमुख खिलाड़ी खेले। मैच की शुरुआत में आर्सेनल ने आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन टोटनहैम ने धीरे-धीरे लय पकड़ते हुए जवाबी हमले किए। 28वें मिनट में विल्सन ओडोबर्ट बॉक्स में घुसे और उनका शॉट पोस्ट से टकरा गया। हाफ टाइम से ठीक पहले, पापे मातर सार ने एक शानदार लॉन्ग-रेंज लॉब शॉट के जरिए टोटनहैम को 1-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में आर्सेनल ने हमलों की रफ्तार बढ़ा दी और कई खतरनाक मौके बनाए। 60वें मिनट के बाद दोनों टीमों ने

कई बदलाव किए। 77वें मिनट में टोटनहैम की ओर से सॉन ह्युंग-मिन और आर्सेनल की ओर से विक्टर ग्योकेरेस मैदान पर आए। दोनों टीमों के जोरदार प्रयासों के बावजूद स्कोर में कोई बदलाव नहीं हुआ और टोटनहैम ने मुकाबला 1-0 से अपने नाम किया।

कनाडियन ओपन 2025: 14 डबल फॉल्ट के बावजूद कोको गॉफ प्री-क्वार्टरफाइनल में

एजेंसी

मॉन्ट्रियल। नेशनल बैंक ओपन (कनाडियन ओपन) में अमेरिका की टॉप सीड और विश्व नंबर-2 कोको गॉफ ने एक बार फिर मुश्किल हालात में शानदार जुझारूपन दिखाया। रूस की वेरोनिका कुदेरमेतोवा के खिलाफ गॉफ ने 14 डबल फॉल्ट किए, लेकिन इसके बावजूद 4-6, 7-5, 6-2 से जीत दर्ज कर प्री-क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई। मैच के बाद गॉफ ने कहा, यह वाकई कठिन मुकाबला था। मैं मानसिक रूप से मजबूत रही, खासकर रिटर्न गेम में। मेरी सर्विस में सुधार की ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल जीत से खुश हूं। फ्रेंच ओपन जीतने के बाद गॉफ बर्लिन और विम्बलडन में अपने शुरुआती मैच हार चुकी थीं। ऐसे में यह जीत उनके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली रही। गॉफ ने कहा, जब मेरा एक हिस्सा कमजोर हो और फिर भी मैं मैच जीत रही हूं, तो सोचिए जब सब कुछ सही चलेगा, तो मैं क्या कर सकूंगी। अब गॉफ का सामना 18 वर्षीय कनाडाई खिलाड़ी विक्टोरिया मबोको

से होगा, जिन्होंने मैरी बौजकोवा को 1-6, 6-3, 6-0 से हराया। मबोको टूर्नामेंट में बची आखिरी कनाडाई खिलाड़ी हैं। इस बीच, अमेरिका की मैकार्टनी केसलर ने चौथी वरीयता प्राप्त रूस की मिर्रा आंद्रेवा को 7-6 (5), 6-4 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। अब केसलर का मुकाबला यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक से होगा, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की 15वीं वरीयता प्राप्त डारिया कसात्किना को 3-6, 6-3, 7-6 (4) से हराया। यूक्रेन की दयाना यास्त्रेम्सका ने आठवीं वरीयता प्राप्त एमा नवारो को 7-5, 6-4 से हराया। अब उनका मुकाबला नौवीं वरीयता प्राप्त कजाकिस्तान की एलेना राइबाकिना से होगा, जिन्होंने रोमानिया की जैकलीन क्रिस्टियन को 6-0, 7-6 (5) से हराया। दसवीं वरीयता प्राप्त यूक्रेन की एलीना स्वितोलिना ने रूस की कमिला राखिमोवा को 7-5, 6-2 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। दो दिन पहले अमेरिकी खिलाड़ी डेनिएल कॉलिन्स के खिलाफ 23 डबल फॉल्ट और तीन सेट के थ्रिलर मैच से गुजरने वाली गॉफ ने इस बार भी एक सेट और ब्रेक से पिछड़ने के बावजूद वापसी की और अपनी लय को कायम रखते हुए अंतिम-16 में प्रवेश किया।

महिला ओपन गोल्फ 2025: वोड की धीमी शुरुआत, ओकायामा और ताकेडा पहले दिन संयुक्त बढ़त पर

एजेंस

पोर्थकोल। महिला ओपन गोल्फ 2025 के पहले दिन इंग्लैंड की लोटी वोड उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकीं, जबकि जापान की एरी ओकायामा और रियो ताकेडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए संयुक्त रूप से बढ़त हासिल की। 21 वर्षीय वोड ने हाल ही में स्कॉटिश ओपन जीतकर प्रोफेशनल करियर की शानदार शुरुआत की थी और इसी कारण उन्हें साल के अंतिम मेजर टूर्नामेंट में फेवरेट माना जा रहा था। लेकिन दक्षिण वेल्स के तटीय मैदान पर उन्हें संघर्ष करना पड़ा और वे आखिरी होल में बर्डी लगाकर सिर्फ लेवल पार (72) का स्कोर ही बना सकीं। जापानी गोल्फरों ने पहले दिन दबदबा कायम रखा। एरी ओकायामा ने 5-अंडर 67 का स्कोर बनाया और बाद में रियो ताकेडा ने 18वें होल में बर्डी कर उनके साथ संयुक्त बढ़त बना ली। मियु यामाशिता 4-अंडर के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि चेम्पियनशिप विजेता माओ साइगो, शिहो कुअकी और चिसातो इवाई 3-अंडर के स्कोर पर हैं। गत विजेता लीडिया को (न्यूजीलैंड) और वर्ल्ड नंबर-1 नेली कोरडा (अमेरिका) भी इस मौके का पूरा फायदा नहीं उठा सकीं। को ने एक ओवर में और कोरडा ने दो अंडर में दिन का खेल समाप्त किया। ओकायामा ने पहले होल में बोगी की लेकिन अगले आठ में से पांच होल में बर्डी कर लय पकड़ ली और 17वें होल में एक और बर्डी लगाकर बढ़त हासिल की। ताकेडा ने नौवें होल में डबल बोगी के बावजूद बैक नाइन में चार बर्डी लगाकर वापसी की। दर्शकों का सबसे ज़्यादा ध्यान दोपहर बाद उस समय गया जब वोड, को और अमेरिका की लीलिया वू के साथ ग्रुप में मैदान में उतरीं। भले ही यह वोड का पहला मेजर टूर्नामेंट था, लेकिन आयरिश ओपन में जीत और एवियन चैंपियनशिप में सिर्फ एक स्ट्रोक से चूकने के बाद वे जब वेल्स पहुंचीं तो उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। वोड ने पहले होल में ही बर्डी से शुरुआत की, लेकिन तीसरे और पांचवें होल में बोगी कर दी। छठे होल में लंबी पुट के जरिए बर्डी जरूर लगाई, लेकिन फिर वे लय में नहीं आ सकीं। नौवें होल में मुश्किल से पार बचाया, जबकि 11वें में बोगी कर बैठीं। हालांकि 14वें होल में शानदार एप्रोच शॉट के बाद बर्डी कर उन्होंने वापसी की कोशिश की, लेकिन 15वें होल में फिर एक शॉट गंवाया। आखिरी होल में बर्डी लगाकर उन्होंने दिन का अंत सकारात्मक रूप से किया।

काकीनाडा में 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कल से, 30 टीमें लेंगी हिस्सा

एजेंसी

नई दिल्ली। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 1 अगस्त से 12 अगस्त तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया जाएगा। इस वर्ष यह प्रतियोगिता एक नए डिवीजन-आधारित प्रारूप में आयोजित की जा रही है, जो इस साल की शुरुआत में सीनियर और सब-जूनियर पुरुष एवं महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी सफलतापूर्वक अपनाया गया था। इस चैंपियनशिप में कुल 30 टीमें भाग लेंगी, जिन्हें प्रदर्शन के आधार पर तीन डिवीजनों–डिवीजन ए, बी और सी–में बांटा गया है। डिवीजन ए और बी की अंतिम स्थान पर रहने वाली टीमें क्रमशः डिवीजन बी और सी में निर्वासित होंगी, जबकि डिवीजन बी और सी की शीर्ष दो टीमें क्रमशः डिवीजन ए और बी में प्रोन्नत होंगी।

डिवीजन ए (शीर्ष स्तरीय

प्रतियोगिता डिवीजन):

डिवीजन ए में देश की शीर्ष 12 टीमें भाग लेंगी। इसमें गत चैंपियन हॉकी झारखंड को पूल ए में, उपविजेता हॉकी मध्य प्रदेश को पूल बी में, और तीसरे स्थान पर रही हॉकी हरियाणा को पूल सी में रखा गया है। डिवीजन ए के मुकाबले 5 अगस्त से शुरू होंगे।

टीमें व पूल संरचना (डिवीजन ए):

पूल ए: हॉकी झारखंड, छत्तीसगढ़ हॉकी, हॉकी कर्नाटक

पूल बी:हॉकी मध्य प्रदेश, हॉकी पंजाब, हॉकी चंडीगढ़

पूल सी: हॉकी हरियाणा, उत्तर प्रदेश हॉकी, हॉकी बंगाल

पूल डी: हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा, हॉकी महाराष्ट्र, हॉकी आंध्र प्रदेश

प्रत्येक पूल में राउंड-रॉबिन प्रारूप में मैच खेले जाएंगे। प्रत्येक पूल की शीर्ष दो टीमें क्वार्टरफाइनल (9 अगस्त), सेमीफाइनल (10 अगस्त) और फाइनल व तीसरे स्थान का मुकाबला (12 अगस्त) में प्रवेश करेंगी। किसी भी वर्गीकरण मैच के ड्रॉ रहने पर एफआईएच नियमों के अनुसार शूट-आउट द्वारा परिणाम तय किया जाएगा।

बेल्ट एण्ड रोड बॉक्सिंग टूर्नामेन्ट में मप्र के भव्य चौधरी करेंगे देश का प्रतिनिधित्व

एजेंसी

भोपाल। चीन के जिनजियांग शहर में आगामी 15 से 30 अगस्त तक बेल्ट एण्ड रोड बॉक्सिंग टूर्नामेन्ट का आयोजन किया जाएगा। इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में मप्र राज्य खेल अकादमी के बॉक्सिंग खिलाड़ी भव्य प्रताप चौधरी 75 कि.ग्रा. भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भव्य प्रताप को इस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में चयनित होने पर बधाई देते हुए बेहतर खेल प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी है। बॉक्सर भव्य प्रताप चौधरी खेल अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक रोशन लाल के मार्गदर्शन में प्रशिक्षणरत् है। उन्होंने बताया कि भव्य प्रताप टूर्नामेन्ट से पहले एक से 15 अगस्त तक रोहतक (हरियाणा) स्थित राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगें। बॉक्सिंग प्रशिक्षण के 15 दिवसीय शिविर के बाद भव्य प्रताप चीन रवाना होंगे।

एफ1: वेरस्टापेन ने की पुष्टि - अगले साल भी रेड बुल के साथ बने रहेंगे

एजेंसी

बुडापेस्ट। चार बार के फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वेरस्टापेन ने अगले सीज़न में मर्सिडीज़ में शामिल होने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। वेरस्टापेन ने हंगेरियन ग्रां प्री से पहले स्पष्ट किया कि वह आगामी वर्ष में भी रेड बुल टीम के साथ ही रेसिंग जारी रखेंगे। उन्होंने पत्रकारों से कहा, मुझे लगता है अब अफवाहों को विराम देने का समय आ गया है। मेरे लिए यह हमेशा स्पष्ट था कि मैं यहीं रहूंगा। टीम में हम लगातार कार के प्रदर्शन को लेकर चर्चा करते रहे हैं। जब आप टीम छोड़ने वाले होते हैं, तो ऐसी बातचीत बंद हो जाती है। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। गौरतलब है कि अगले साल से फॉर्मूला वन में इंजन नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मर्सिडीज़ के इस नए युग में अग्रणी रहने की संभावना जताई जा रही है, वहीं रेड बुल अपनी नई पावर यूनिट पर काम कर रही है, जो अब होंडा से अलग हो चुकी है। हालांकि

वेरस्टापेन के अनुबंध में ब्रेक क्लॉज शामिल हैं, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया है। इस सीज़न में 13 रेसों में दो जीत के साथ वह मिड-सीज़न में तीसरे स्थान पर हैं। उनका रेड बुल के साथ अनुबंध 2028 तक है। रेड बुल टीम बॉस क्रिश्चियन हॉर्नर की हालिया बर्खास्तगी को भी वेरस्टापेन को टीम में बनाए रखने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। वेरस्टापेन ने कहा, कुछ लोग सिर्फ नाटक करना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे लिए यह हमेशा से साफ था।

वहीं, मर्सिडीज़ के बॉस टोतो वोल्फ ने हाल ही में संकेत दिया था कि उनकी प्राथमिकता वर्तमान ड्राइवर लाइनअप - जॉर्ज रसेल और इटालियन ड्राइवर किमी एंटोनेली - को बनाए रखने की है।

जॉर्ज रसेल ने भी अलग से कहा, मैं अगले साल मर्सिडीज़ के लिए ही दौड़ूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अनुबंध पर दस्तखत अगस्त ब्रेक के बाद ही होंगे रसेल, जो 16 साल की उम्र से मर्सिडीज़ की मैनेजमेंट के तहत हैं, ने बताया कि वह और वोल्फ इस समय टीम के प्रदर्शन सुधार पर ध्यान दे रहे हैं, न कि अनुबंध पर। उन्होंने कहा, अभी मेरे और मर्सिडीज़ के लिए अनुबंध को लेकर कोई जल्दीबाज़ी नहीं है।,

काउंटी चैम्पियनशिप 2025: साई किशोर ने सरे के लिए झटके पांच विकेट, चहल और तिलक वर्मा भी चमके

एजेंसी

नई दिल्ली। तमिलनाडु के बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर आर. साई किशोर ने काउंटी चैम्पियनशिप 2025 के मुकाबले में सरे की ओर से खेलते हुए डरहम के खिलाफ शानदार पांच विकेट झटके। यह मुकाबला रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जा रहा है। साई किशोर ने मैच के दूसरे दिन दो विकेट चटकाए थे, जिसके बाद तीसरे दिन कोडी यूसुफ, बास डी लीडे और मैथ्यू पॉट्स को आउट कर उन्होंने पांच विकेट (5/72) पूरे किए। उन्होंने मैच में कुल सात विकेट लिए और अब तक दो मैचों में 11 विकेट 24 की औसत से झटके हैं।

उनकी शानदार गेंदबाज़ी के दम पर सरे ने डरहम को 344 रनों पर ऑलआउट कर दिया, जिससे जीत के लिए उन्हें केवल 176 रनों का लक्ष्य मिला। डिवीजन टू में खेलते हुए, युजवेंद्र चहल ने नॉर्थहैम्पटनशायर की ओर से डर्बीशायर के खिलाफ चौथे दिन दो विकेट झटके। उन्होंने पहली पारी में छह विकेट लिए थे और अब मैच में उनके आठ विकेट हो गए हैं। यदि वह अंतिम दिन दो और विकेट लेते हैं तो उनके नाम मैच में 10 विकेट हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह रही कि चहल ने लगातार दो गेंदों पर दो विकेट लेकर हैट्रिक की स्थिति बना दी थी, लेकिन वेन मैडसेन ने तीसरी गेंद को संभाल लिया। वहीं, हैम्पशायर

की ओर से खेल रहे तिलक वर्मा ने वोर्सेस्टरशायर के खिलाफ 62 गेंदों में नाबाद 33 रन बनाए। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक हैम्पशायर ने 139/2 का स्कोर बना लिया था और उनकी लीड 183 रन हो गई है।

डीपीएल 2025: पुरानी दिल्ली-6 ने वंश बेदी को बनाया कप्तान, टीम को खिताब जीतने की उम्मीद

एजेंसी

दिल्ली। दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) के बहुचर्चित दूसरे सीजन से पहले पुरानी दिल्ली-6 फ्रेंचाइजी ने युवा और प्रतिभाशाली विकेटकीपर-बल्लेबाज वंश बेदी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 02 अगस्त को राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगी, जबकि पुरानी दिल्ली-6 अपना पहला मुकाबला 05 अगस्त को आउटर दिल्ली वॉरियर्स के खिलाफ खेलेगी।पिछले सीजन में सेमीफाइनल तक का सफर तय करने वाली टीम इस बार खिताबी जीत को लक्ष्य बनाकर मैदान में उतरने जा रही है। वंश बेदी ने घरेलू सत्र में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया और अब उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीम के मालिक आकाश नांगिया ने कहा, 'वंश में जुनून है, नेतृत्व की समझ है और क्रिकेट के प्रति समर्पण है। हमें पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में टीम सिर्फ अच्छा प्रदर्शन ही नहीं करेगी, बल्कि 'पुरानी दिल्ली' की भावना को भी मैदान पर उतारेगी। इस बार प्यूमा टीम की आधिकारिक जर्सी पार्टनर बनी है, जबकि रेडियो मिर्ची को ऑफिशियल रेडियो पार्टनर के रूप में जोड़ा गया है। यह सहयोग टीम की लोकप्रियता और ब्रांड वैल्यू में और इजाफा करेगा।

डीपीएल 2025: खिताबी जीत के इरादे से मैदान में उतरने को तैयार टीमें, कप्तानों में दिखा जोश

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रीमियर लीग(डीपीएल) के बहुप्रतीक्षित दूसरे संस्करण की शुरुआत 02 अगस्त को प्रतिष्ठित अरुण जेटली स्टेडियम में होगी। उद्घाटन मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़ और ईस्ट दिल्ली राइडर्स आमने-सामने होंगी। टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ही खिलाड़ियों और दर्शकों में रोमांच चरम पर है।

टीमों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं व सभी कप्तान खिताब को लेकर अपने-अपने इरादों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट और उत्साहित नजर आ रहे हैं।नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान और तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने टीम की एकजुटता और मेहनत की सराहना करते हुए कहा, जब पहली बार मैदान पर कदम रखा और टीम से मिला, तो दिल से खुशी हुई। मेरा सपना था कि सब एकजुट होकर पूरे जुनून से अभ्यास करें। कई खिलाड़ी दूर-दूर से यहां आते हैं और उनका समर्पण देखकर मुझे गर्व महसूस होता है। ईस्ट दिल्ली राइडर्स के कप्तान अनुज रावत ने अनुभवी तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की तारीफ करते हुए कहा, सैनी जैसे सीनियर खिलाड़ी का समर्पण काबिल-ए-तारीफ है। वह निरंतर मेहनत कर रहे हैं और हर खिलाड़ी जीत के लिए प्रतिबद्ध है। पूरी टीम एकजुट है और यही हमारी ताकत है। वेस्ट दिल्ली लायंस के कप्तान नितीश राणा ने टीम में मौजूद युवा प्रतिभाओं पर भरोसा जताते हुए कहा, दो साल बाद लौटना मेरे लिए खास रहा। टीम में अंडर-19, अंडर-23 और अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिनकी प्रतिभा ने मुझे हैरान कर दिया। इतने मैच विनर्स के साथ मैदान में उतरना एक कप्तान के लिए सौभाग्य की बात है।

साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़ के कप्तान आयुष बडोनी ने अपनी टीम की नीलामी को लेकर संतोष जताया। उन्होंने कहा, नीलामी हमारे लिए बेहद सफल रही। जिन खिलाड़ियों पर नजर थी, उन्हें हम टीम में लाने में सफल रहे। टीम का माहौल शानदार है और हर खिलाड़ी खिताब के लिए प्रतिबद्ध है।पुरानी दिल्ली 6 के कप्तान वंश बेदी ने कहा, टीम के बीच गजब की एकता है, मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह। खिलाड़ी एक-दूसरे के खेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो लंबे टूर्नामेंट में बेहद अहम होता है। आउटर दिल्ली वॉरियर्स के कप्तान सिद्धांत शर्मा ने बताया,नीलामी से हमें मनचाहे खिलाड़ी मिले, जिससे आत्मविश्वास बढ़ा है। टीम में जबरदस्त ऊर्जा है और हर कोई एक ही दिशा में मेहनत कर रहा है- हमारा लक्ष्य सिर्फ खिताब है। न्यू दिल्ली टाइगर्स के कप्तान हिम्मत सिंह ने कहा, टीम पूरी तरह तैयार है और सपोर्ट स्टाफ व प्रबंधन की ओर से शानदार सुविधाएं मिली हैं। इससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए जरूरी माहौल मिला है। सेंट्रल दिल्ली किंग्स के कप्तान जांटी सिद्धू ने मैदान की तैयारियों और टीम संतुलन की तारीफ करते हुए कहा, मौसम की चुनौतियों के बावजूद हमारे ग्राउंड स्टाफ ने शानदार काम किया है। हमारी टीम संतुलित है और हर विभाग में मजबूत दिख रही है। इस बार का डीपीएल न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि दिल्ली के क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी एक बड़ा मंच साबित होने वाला है। हर कप्तान की नजर एक ही लक्ष्य ड़ीपीएल 2025 की ट्रॉफी पर है।

सर्राफा बाजार में सस्ता हुआ सोना, चांदी की भी घटी चमक

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में अगस्त के पहले दिन आज गिरावट का रुख नजर आ रहा है। सोना आज 420 रुपये से 470 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। इसी तरह चांदी के भाव में भी आज 2,200 रुपये प्रति किलोग्राम तक की गिरावट आई है। कीमत में कमी आने के कारण आज देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 1,00,020 रुपये से लेकर 1,00,170 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी आज 91,690 रुपये से लेकर 91,840 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। सोने की तरह चांदी के भाव में भी कमी आने के कारण कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,14,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,00,170 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 91,840 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,00,020 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 91,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,00,070 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 91,740 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत का दूरसंचार निर्यात प्रतिस्पर्धी बना रहेगा: सिंधिया

नई दिल्ली। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अतिरिक्त टैरिफ (शुल्क) लगाए जाने के बाद भी अमेरिका में भारतीय दूरसंचार उपकरणों का निर्यात प्रतिस्पर्धी बना रहेगा। उन्होंने प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ के दूरसंचार उपकरणों के निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर कहा, हम प्रतिस्पर्धी बने रहेंगे। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सिंधिया ने भारत में पहली सेलुलर कॉल की 30वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली स्थित होटल ले मेरिडियन में कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट), ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (एआईएमआरए और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एसोसिएशन (ओरा) के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में डिजिटल क्रांति आ गई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति के चलते यूपीआई के जरिए 2.5 बिलियन लेन-देन प्रतिवर्ष हो रहे हैं। हम 4जी उपकरण खुद बनाने वाले 5वें देश बन गए हैं, अब 6जी में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन से 6.5 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए 17 बिलियन डॉलर का निवेश होगा।

स्वास्थ्य सेवा और आवास नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डीपीआईआईटी का एचडीएफसी कैपिटल से करार

नई दिल्ली। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। डीपीआईआईटी ने यह समझौता किफायती आवास और प्रॉपटेक क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए किया है। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर औपचारिक रूप से डीपीआईआईटी के निदेशक मोहम्मद इशरार अली और एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ विपुल रूंगटा ने दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक इस साझेदारी का उद्देश्य आवासीय रियल एस्टेट विकास चक्र में दक्षता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए एचडीएफसी कैपिटल की पहल का हिस्सा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किफायती आवास विकास पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जुड़ाव, उभरती हुई प्रॉपटेक कंपनियों में रणनीतिक निवेश और त्वरक, शैक्षणिक संस्थानों और निवेशकों के सहयोग से मार्गदर्शन के माध्यम से विकास के अवसरों को सुगम बनाना है।

डॉलर की तुलना में कमजोर हुआ रुपया, 16 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुई भारतीय मुद्रा

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ और जुर्माना लगाने का ऐलान करने का असर आज भी भारत के मुद्रा बाजार में साफ-साफ नजर आया। मुद्रा बाजार में बने नकारात्मक माहौल और घरेलू शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण रुपया आज एक बार फिर डॉलर की तुलना में गिरावट का शिकार हो गया। आज डॉलर की तुलना में भारतीय मुद्रा 16 पैसे फिसल कर 87.60 (अनंतिम) के स्तर पर बंद हुई। इसके पहले पिछले कारोबारी दिन भारतीय मुद्रा 87.44 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई थी। रुपये ने आज के कारोबार की शुरुआत भी गिरावट के साथ ही की थी। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारतीय मुद्रा ने आज सुबह डॉलर के मुकाबले 25 पैसे की कमजोरी के साथ 87.69 रुपये के स्तर से कारोबार की शुरुआत की थी। आज का कारोबार शुरू होने के कुछ देर बाद ही बाजार में बने नकारात्मक माहौल के कारण रुपया 31 पैसे की गिरावट के साथ 87.75 के स्तर तक पहुंच गया। हालांकि, दोपहर 12 बजे के बाद स्टॉक मार्केट की जोरदार रिकवरी के कारण विदेशी निवेशकों ने भी लिवाली शुरू कर दी।

जबरदस्त उतार-चढ़ाव के बाद गिरा घरेलू शेयर बाजार, निवेशकों को लगी 2.59 लाख करोड़ की चपत

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार आज जबरदस्त उतार-चढ़ाव का गवाह बना। आज के कारोबार की शुरुआत बड़ी गिरावट के साथ हुई थी। दिन के पहले सत्र में लगातार दबाव बना रहा, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद खरीदारों ने आक्रामक अंदाज में लिवाली करके शेयर बाजार को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। सेंसेक्स निचले स्तर से 1,100 अंक से अधिक उछल गया। इसी तरह निफ्टी निचले स्तर से 320 अंक से अधिक की छलांग लगाने में सफल रहा। हालांकि मंथली एक्सपायरी की वजह से आखिरी 1 घंटे के कारोबार में बिकवाली का दबाव बन जाने के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक एक बार फिर लाल निशान में गिर गए। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.36 प्रतिशत और निफ्टी 0.35 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुए। आज दिन भर के कारोबार के दौरान फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस और मेटल सेक्टर के शेयरों में जम कर बिकवाली होती रही। इसी तरह पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, आईटी, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल और टेक इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए। दूसरी ओर, एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में आज खरीदारी होती रही। ब्रॉडर मार्केट में भी आज लगातार बिकवाली होती रही, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.70 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.85 प्रतिशत की कमजोरी के साथ आज के कारोबार का अंत किया।आज शेयर बाजार में आई कमजोरी के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद घट कर 449.70 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया। जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 452.29 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 2.59 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो गया।आज दिन भर के कारोबार में बीएसई में 4,153 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 1,606 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2,411 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं 136 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,658 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 872 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में और 1,786 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 8 शेयर बढ़त के साथ और 22 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 13 शेयर हरे निशान में और 37 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स आज 786.36 अंक की कमजोरी के साथ 80,695.50 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होने के बाद से ही खरीदारों ने लिवाली का जोर बनाने की कोशिश शुरू कर दी, जिससे इस सूचकांक की चाल में सुधार होना शुरू हो गया। दोपहर 12 बजे के बाद खरीदारों ने लिवाली और तेज कर दी, जिसकी वजह से दोपहर 2 बजे के करीब सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से 1,108.12 अंक उछल कर 321.41 अंक की मजबूती के साथ 81,803.27 अंक तक पहुंच गया। हालांकि ये तेजी अधिक देर तक टिक नहीं सकी। इसके बाद मंथली एक्सपायरी की वजह से बाजार में बिकवाली शुरू हो गई।

ईडी ने अनिल अंबानी को भेजा समन, 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस समूह के चेयरमैन और एमडी अनिल अंबानी को 17 हजार करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनको 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अनिल अंबानी को भेजे गए समन में नई दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है, क्योंकि मामला यहीं दर्ज किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत उनके बयान दर्ज किये जाएंगे।अनिल अंबानी को यह समन पिछले हफ्ते केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से उनके व्यावसायिक समूह की कई कंपनियों और अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी के बाद जारी किया गया है। 24 जुलाई को शुरू हुई ईडी की यह छापेमारी तीन दिनों तक मुंबई में 35 से अधिक ठिकानों पर चली थी, जिनमें 50 कंपनियां और 25 लोग शामिल थे, इनमें अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के कई अधिकारी भी शामिल थे।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सिंगापुर यात्रा सफल, 45,000 करोड़ के निवेश समझौतों पर हुए हस्ताक्षर : नारा लोकेश

एजेंसी

अमरावती। राज्य के आईटी और उद्योग मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सिंगापुर यात्रा सफल रही और पांच वर्षों में 45,000 करोड़ रुपये के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मंत्री ने सचिवालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि वे समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्हें सीधे लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्सेलर मित्तल को ज़ूम कॉल के ज़रिए निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। आर्सेलर मित्तल लक्ज़मबर्ग स्थित एक बहुराष्ट्रीय इस्पात निर्माण कंपनी है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी है। लोकेश ने खुलासा किया कि देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट और डेटा सेंटर आंध्र प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है। लोकेश का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 2019 से 2024 के बीच आंध्र प्रदेश ब्रांड को बर्बाद कर दिया। चंद्रबाबू की सरकार 2014 में राज्य के पुनर्गठन के बाद सिंगापुर ने

अमरावती के संयुक्त विकास के लिए हर कदम उठाए और राजधानी के निर्माण के लिए समझौता भी किया था लेकिन पिछली सरकार ने बिना सोचे समझे अलग नीति अपनाकर किसी के भी बात सुने बिना समझौते रद्द कर दिए।मंत्री लोकेश ने कहा कि पारदर्शिता के मामले में विश्व में सिंगापुर सबसे आगे है। ऐसे देश को जगन ने भ्रष्ट करार दिया था। जगन की सरकार ने अमरराजा बैटरीज और लुलु समेत कई कंपनियों को भगा दिया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू हैं जो नई राजधानी अमरावती के लिए पूरा जुड़ गए हैं। हमने वर्तमान में विशाखापत्तनम को आईटी के नक्शे पर लाने का फैसला किया है। इससे राज्य का विकास दस गुना होने की अपेक्षा है। लोकेश ने कहा कि हमने टीसीएस को 99 रुपये प्रति एकड़ की दर से ज़मीन आवंटित की, जो किसी भी राज्य ने नहीं दी। वाईएसआरसीपी के नेता इस मामले को लेकर अदालत गए। इससे राज्य के युवा को नौकरियां आएंगी। इसमें क्या ग़लत है? हमारी सरकार ने 14 महीनों में जो निवेश किया है, वह वाईएसआरसीपी द्वारा किए गए निवेश से ज़्यादा है।

स्टॉक मार्केट में श्री रेफ्रिजरेशंस की जोरदार एंट्री, 40 प्रतिशत मुनाफे में आईपीओ निवेशक

एजेंसी

नई दिल्ली। एचवीएसी सिस्टम्स बनाने वाली कंपनी श्री रेफ्रिजेरेशंस के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जोरदार एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 125 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 35.88 प्रतिशत प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग 169.85 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद लिवाली शुरू हो जाने के कारण सुबह 11 बजे तक कंपनी के शेयर उछल कर 175 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। इस तरह अभी तक के कारोबार में कंपनी के आईपीओ निवेशकों को लगभग 40 प्रतिशत का मुनाफा हो चुका है। श्री रेफ्रिजेरेशंस का 117.33 करोड़ रुपये का आईपीओ 25 से 29 जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 187.55 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन

167.32 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 197.01 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 195.05 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 94.52 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए हैं। इसके अलावा 2 रुपये फेस वैल्यू वाले 18.25 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिए बेचे गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 2.57 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 11.53 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 13.55 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्व 39 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ कर 99.01 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

सेलोरैप इंडस्ट्रीज की स्टॉक मार्केट में जोरदार एंट्री, लिस्टिंग के बाद लगा अपर सर्किट

एजेंसी

नई दिल्ली। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी सेलोरैप इंडस्ट्रीज के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जोरदार एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 83 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 8.43 प्रतिशत प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग 90 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद लिवाली शुरू हो जाने के कारण इस शेयर की चाल में तेजी आ गई। लगातार हो रही लिवाली के कारण दोपहर 12 बजे के करीब सेलोरैप इंडस्ट्रीज के शेयर उछल कर 94.50 रुपये के अपर सर्किट लेवल तक पहुंच गए। इस तरह कंपनी के आईपीओ निवेशकों को पहले दिन ही 13.86 प्रतिशत का मुनाफा हो चुका है। सेलोरैप इंडस्ट्रीज का 30.28 करोड़ रुपये का आईपीओ 25 से 29

जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 65.09 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 18.76 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 117.81 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। ये पूरा आईपीओ फ्रेश शेयरों का था। इसके तहत कुल 36.48 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। सेलोरैप इंडस्ट्रीज की ये लिस्टिंग ग्रे मार्केट की उम्मीदों से थोड़ी बेहतर रही। लिस्टिंग से पहले सेलोरैप इंडस्ट्रीज के शेयर अनलिस्टेड मार्केट में करीब 6 प्रतिशत के ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे थे। ऐसे में आज ग्रे मार्केट प्रीमियम से ऊंचे स्तर पर हुई लिस्टिंग से आईपीओ निवेशकों को तुलनात्मक रूप से अधिक फायदा हुआ है। इस इश्यू का बुक रनिंग लीड मैनेजर ग्रेटेक्स कॉरपोरेट सर्विसेज था। वहीं पूर्वा शेयरेगिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया था।

मजबूत लिस्टिंग के बाद बिकवाली के दबाव में लुढ़के पटेल केम के शेयर

एजेंसी

नई दिल्ली। फार्मास्युटिकल एक्सीपीएंट्स और स्पेशियलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी पटेल केम स्पेशियलिटीज लिमिटेड के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जोरदार एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। हालांकि, लिस्टिंग के बाद बिकवाली शुरू हो जाने के कारण निवेशकों की खुशी फीकी पड़ गई। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 84 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 31 प्रतिशत प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग 110 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद बिकवाली शुरू हो जाने के कारण इस शेयर की चाल में गिरावट आ गई। लगातार हो रही बिकवाली के कारण दोपहर 12 बजे के करीब पटेल केम स्पेशियलिटीज के शेयर फिसल कर 104.55 रुपये के स्तर तक पहुंच गए। इस गिरावट के बावजूद कंपनी के आईपीओ निवेशकों को अभी तक के कारोबार में 24.46 प्रतिशत का मुनाफा हो चुका है। पटेल केम स्पेशियलिटीज लिमिटेड का 59 करोड़ रुपये का आईपीओ 25 से 29 जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 167 गुना सब्सक्राइब हुआ था। ये पूरा आईपीओ फ्रेश शेयरों का था। इसके तहत कुल 70 लाख शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। पटेल केम स्पेशियलिटीज लिमिटेड की ये लिस्टिंग ग्रे मार्केट की उम्मीदों के मुताबिक ही रही। ग्रे मार्केट के आंकड़ों के अनुसार लिस्टिंग से पहले कंपनी के शेयर अनलिस्टेड मार्केट में करीब 111 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे।

छत्तीसगढ़ को मिली 600 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात

एजेंसी

रायपुर। छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना को रफ्तार देने के लिए आज एक अहम क़दम उठाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाक़ात की, जिसमें राज्य की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली। बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 600 करोड़ रुपये की मंज़ूरी। इसके ज़रिए छत्तीसगढ़ में कई सड़कों के निर्माण और उन्नयन का रास्ता साफ़ हुआ है। इसके साथ ही स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत आने वाले दो लेन मार्ग को चार लेन में अपग्रेड करने की योजना को भी मंज़ूरी मिली है।रायपुर शहर की भीड़भाड़ को कम करने के लिए चार बड़े ब्रिज बनाए जाएंगे, जिनका भूमि पूजन शीघ्र ही होगा। वहीं, राजधानी रायपुर से अन्य ज़िलों तक की सड़कें दो लेन से चार लेन में बदली जाएंगी, जिससे आवागमन तेज़ और सुरक्षित हो जाएगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि राज्य की सभी सड़क योजनाएं अब केंद्र के 'गति शक्ति पोर्टल' के ज़रिए भेजी जाएंगी, ताकि जल्द मंज़ूरी मिल सके। श्री गडकरी ने रायपुर (आरंग)-बिलासपुर (दर्री) के बीच करीब 95 किमी लंबी छह लेन सड़क के लिए डीपीआर भेजने को कहा, जो औद्योगिक, कृषि और शैक्षिक क्षेत्रों को जोड़ेगी। साथ ही, नागपुर से रायपुर तक प्रस्तावित 300 किमी लंबा समृद्धि एक्सप्रेसवे पर भी शीघ्र डीपीआर मांगा गया है।इसके अलावा कुछ ज़रूरी योजनाओं को आज मंज़ूरी भी मिल गई। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 ए में उन्नयन कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 में रेजिंग का कार्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में मजबूतीकरण के कुल 115.95 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति मिली है। इनमें बिलासपुर शहर के भीतर 15 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शामिल है, जिससे शहर में ट्रैफिक आसान होगा। कटनी-गुमला मार्ग के हिस्से में 11 किलोमीटर सड़क बनेगी जो गांवों को जोड़ने में मदद करेगी। वहीं, केशकाल के 4 किलोमीटर हिस्से की सड़क को मज़बूत किया जाएगा, जिससे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 7000 करोड़ रुपये से ऊपर के नियोजित कार्यो की वित्तीय स्वीकृति को भी शीघ्र करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सड़कें केवल यात्रा का साधन नहीं हैं बल्कि विकास, रोज़गार और सामाजिक बदलाव का रास्ता हैं। अंजोर विजन 2047' के तहत छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव, हर नागरिक तक बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन पहुंचे। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह भी उपस्थित थे।

शांति गोल्ड की स्टॉक मार्केट में प्रीमियम लिस्टिंग, फायदे में आईपीओ निवेशक

एजेंसी

नई दिल्ली। रत्नाभूषण का काम करने वाली कंपनी शांति गोल्ड के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में मजबूत एंट्री की। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 199 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 229.10 रुपये के स्तर पर और एनएसई पर 227.55 रुपये के स्तर पर हुई। इस तरह आईपीओ निवेशकों को शुरू में ही करीब 15 प्रतिशत का लिस्टिंग गेन मिल गया। लिस्टिंग के बाद लिवाली शुरू हो जाने के कारण सुबह 11 बजे तक कंपनी के शेयर उछल कर 230.25 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। इस तरह अभी तक के कारोबार में कंपनी के आईपीओ निवेशकों को लगभग 15.70 प्रतिशत का मुनाफा हो चुका है। शांति गोल्ड का 300.13 करोड़ रुपये का आईपीओ 25 से 29 जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 80.78 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 117.33 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 151.17 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 29.73 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 1,80,96,000 नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने जयपुर में प्रस्तावित फैसिलिटी का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने. वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 19.82 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 26.87 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 65.84 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्व 27 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ कर 1,112.47 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

एनएसडीएल का आईपीओ 760-800 रुपये प्राइस बैंड के साथ खुला, एक अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

एजेंसी

जयपुर। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) का बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 30 जुलाई को निवेशकों के लिए खुल गया है और यह 1 अगस्त को बंद होगा। यह निर्गम पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के रूप में जारी किया गया है, जिसमें कंपनी की ओर से कोई नया शेयर जारी नहीं किया जा रहा है। इस आईपीओ के अंतर्गत कुल 50,145,001 इक्विटी शेयरों की बिक्री की जा रही है। यह बिक्री आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम जैसे मौजूदा शेयरधारकों द्वारा की जा रही है। कंपनी ने 2 रुपये के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों के लिए 760 से 800 रुपये प्रति शेयर का मूल्य बैंड तय किया है। निवेशक न्यूनतम 18 शेयरों और उसके बाद 18 के गुणकों में आवेदन कर सकते हैं। एंकर निवेशकों के लिए बोली प्रक्रिया 29 जुलाई को पूरी हो चुकी है, जबकि अन्य निवेशक 1 अगस्त तक बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ के अंतर्गत सभी आवेदन अनिवार्य रूप से एएसबीए (एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट) प्रक्रिया के माध्यम से किए जाएंगे।

टेक्सटाइल उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए होंगे हरसंभव प्रयासः मुख्यमंत्री डॉ यादव

एजेंसी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक और गुणवत्तापूर्ण कपास उत्पादन करने वाला राज्य है। राज्य सरकार ने कपास से धागा, कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। न केवल देश बल्कि अन्य देशों की टेक्सटाइल इकाइयों से भी अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर बायर-सेलर के साथ चर्चा को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉ यादव नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट में उद्योगपतियों को संबोधित कर रहे थे। समिट में देश-दुनिया के कई इंडस्ट्री लीडर्स उपस्थित हुए। समिट में राज्य सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों के साथ निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर वन-टू-वन मीटिंग भी की। इन प्रयासों से मध्य प्रदेश में निवेश आएगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश उद्योग प्रोत्साहक राज्य की छवि बनाते हुए सभी सेक्टर्स के उद्यमियों को आमंत्रित कर रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समिट में उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स का स्वागत करते हुए कहा कि देश ऐसे ही नहीं बदलता है, इसके लिए दृढ़ संकल्पों की आवश्यकता होती है। इन संकल्पों में नवीनता होती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सभी प्रकार के व्यवसायों को आगे बढ़ा रही है। औद्योगीकरण को गति प्रदान करने में बायर-सेलर वर्ग का विशेष स्थान होता है। प्रधानमंत्री मोदी के देश की बागडोर संभालने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।

ईज ऑफ डूइंग के अंतर्गत 42 कानूनों को किया खत्म

उन्होंने कहा कि सरकार ने ईज ऑफ डूइंग के अंतर्गत 42 कानूनों को खत्म किया है, जो व्यापार में बाधा बनते थे। राज्य सरकार ने उद्योग शुरू करने के लिए जरूरी 29 अनुमतियों को भी कम करके 10 तक सीमित कर दिया है। प्रदेश में उद्योगपतियों को बिजली, पानी, जमीन सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्रमिकों के वेतन के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है। मेक इन इंडिया से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज हमें प्रतिकूलता से आगे बढ़कर अनुकूलता की ओर बढ़ने की जरूरत है। राज्य सरकार ने डेढ़ साल के कार्यकाल में औद्योगीकरण का वातावरण तैयार किया है। सरकार खनन, पर्यटन, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में नवाचारों के साथ आगे बढ़ रही है।

टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल और गारमेंट्स सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं है। मध्य प्रदेश में हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के आर्टिजंस और छोटे-छोटे उद्योग उपलब्ध है। राज्य की चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियों ने देश में ही नहीं, विदेश में भी अपनी पहचान बनाई है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम निरंतर कार्यरत हैं। राज्य में निवेशकों को वित्तीय एवं गैर वित्तीय सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। वित्तीय प्रोत्साहन निवेशकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने की सुविधा है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य में निवेश करने पर सरकार सभी नीतियों का पूर्ण लाभ प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4000 से अधिक दिनों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है। हम सभी प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया के लक्ष्य को मिलकर पूरा कर सकते हैं। राज्य सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले यूरोपीय देशों की संख्या बढ़ने पर एर्दोगन ने की सराहना

एजेंसी

अंकारा। तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने हाल के दिनों में फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल द्वारा फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम यूरोपीय देशों की ओर से मानवीय भावना और न्याय की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण निर्णय है। एर्दोगन ने बताया कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से हाल ही में बातचीत की, जिन्होंने पिछले सप्ताह फ्रांस की ओर से फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की थी। इसके बाद ब्रिटेन, कनाडा (और पुर्तगाल ने भी इसी राह पर कदम बढ़ाया। राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा, हमें यूरोप से खासकर फ्रांस और ब्रिटेन से आ रही मानवीय प्रतिक्रियाएं अत्यंत मूल्यवान लगती हैं। हम फिलिस्तीन को मान्यता देने की दिशा में उठाए गए हर कदम का स्वागत करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तुर्किये आने वाले दिनों में इजराइल पर और अधिक दबाव बनाएगा ताकि ग़ाजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि कोई भी गाजा में हो रहे अत्याचारों पर चुप नहीं रह सकता, जहां बच्चे भूख से मर रहे हैं और खाना ढूंढ रहे आम नागरिकों पर जानबूझकर गोली चलाई जा रही हैं। एर्दोगन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की है कि वे इस गंभीर मानवीय संकट के समाधान के लिए सक्रिय हस्तक्षेप करें और दो-राज्य समाधान की दिशा में ठोस पहल करे।

ट्रंप ने मेक्सिको के साथ व्यापार समझौते की समयसीमा 90 दिनों के लिए बढ़ाई

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि मेक्सिको के साथ व्यापार समझौते को लेकर तय 01 अगस्त की डेडलाइन को 90 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय ट्रंप और मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाउम के बीच हुई टेलीफोनिक बातचीत के बाद लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रूथ सोशल' पर पोस्ट में लिखा, 'मेक्सिको 25 फीसदी फेंटानिल टैरिफ, 25 फीसदी कारों पर टैरिफ और 50 फीसदी स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर पर टैरिफ देना जारी रखेगा। इसके अलावा, मेक्सिको ने अपने कई गैर-शुल्क व्यापार अवरोध को तुरंत समाप्त करने पर सहमति जताई है। उन्होंने आगे कहा कि अगले 90 दिनों में अमेरिका और मेक्सिको के बीच बातचीत जारी रहेगी, ताकि एक औपचारिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकें। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने भी एक्स पर पोस्ट में कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। हमने कल घोषित टैरिफ वृद्धि को टाल दिया और बातचीत के जरिए दीर्घकालिक समझौता करने के लिए 90 दिन का समय हासिल कर लिया।

कीव पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 9 की मौत, 124 घायल

कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने रातभर मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से भीषण हमला किया, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 124 अन्य घायल हो गए। मारे गए लोगों में 6 साल का एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 10 बच्चे घायल हुए हैं जिनमें सबसे छोटी 5 महीने की बच्ची है। कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख तिमुर त्काचेंको ने बताया कि एक नौ मंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा हमले में ढह गया। स्थानीय निवासी याना जब्बोरोवा (35) ने बताया कि जब विस्फोट हुआ, तो घर की खिड़कियां और दरवाज़े उड़ गए। अब तो बस सदमा और तनाव ही बाकी है, क्योंकि और कुछ भी नहीं बचा है। यूक्रेनी वायु सेना के मुताबिक, रूस ने कुल 309 शहीद ड्रोन और 8 इस्कंदर-के क्रूज मिसाइलें दागीं। इनमें से 288 ड्रोन और 3 मिसाइलों को यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया, लेकिन 21 ड्रोन और 5 मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच गईं और भारी तबाही मचाई। हमले में कीव, द्नीप्रो, पोल्टावा, सुमी और मिकोलेव क्षेत्र निशाना बने, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव कीव पर पड़ा। राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर कहा, आज दुनिया ने फिर देखा कि अमेरिका और यूरोप के साथ हमारी शांति की इच्छा का रूस ने कैसा उत्तर दिया। इसलिए शांति केवल ताकत के साथ ही संभव है।

पाकिस्तान में पीटीआई के कई नेताओं को नौ मई के मामलों में 10 साल जेल की सजा

इस्लामाबाद। अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान की खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कई नेताओं को आज 2023 के विरोध प्रदर्शनों से संबंधित मामलों में सजा सुनाई गई। फैसलाबाद स्थित एक विशेष आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने इन नेताओं को 10 साल तक की जेल की सजा सुनाई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब, सीनेट में विपक्ष के नेता शिबली फराज, जरताज गुल, एमएनए साहिबजादा हामिद रजा और पूर्व एमएनए शेख राशिद शफीक, पूर्व गृहमंत्री शेख रशीद अहमद के भतीजे उन 108 पीटीआई नेताओं में शामिल हैं, जिन्हें इन दोषी ठहराया गया, जबकि 77 अन्य को बरी कर दिया गया। एटीसी ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल और हामिद रजा सहित लगभग 60 दोषियों को 10 साल और अन्य दोषियों को तीन साल की जेल की सजा सुनाई। एटीसी ने पीटीआई नेता फवाद चौधरी के साथ जैन कुरैशी, ख्याल कास्त्रो, फैजुल्लाह कमोका, राणा असद महमूद खान, बिलाल अशरफ बसरा, हारून रशीद, अमारा रशीद, साहिबजादा हसन रजा और कामरान वराइच को बरी कर दिया गया।

वाशिंगटन में दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री: मार्को रुबियो से की मुलाकात, ट्रेड डील को लेकर हुई बात

एजेंसी

वाशिंगटन। दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री चो ह्यून वाशिंगटन में अपने समकक्ष मार्को रुबियो से मुलाकात की। दोनों ने ट्रेड डील समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति जल्द ही एक शिखर सम्मेलन में शामिल होने अमेरिका आएंगे, उन तैयारियों का भी जायजा लेने ह्यूयन अमेरिका पहुंचे हैं। चो ह्यून और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि दो सप्ताह बाद वे व्हाइट हाउस में कोरियाई राष्ट्रपति ली से मुलाकात कर एक नए ट्रेड डील को आकार देंगे। योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, चो और रुबियो की इस मुलाकात में कई विषयों पर गंभीर चर्चा हुई। इसमें उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे, द्विपक्षीय संबंधों को

बेहतर करने और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर समन्वय को लेकर मंत्रणा की गई। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने एक प्रेस ब्रीफिंग में इस बैठक की जानकारी दी और अमेरिका-कोरिया व्यापार समझौते पर भी टिप्पणी की।

पिगॉट ने कहा, ÷यह व्यापार समझौता, जो आज विदेश मंत्री रुबियो और कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून की बैठक के साथ हुआ है, अमेरिका-आरओके गठबंधन की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। यह गठबंधन पिछले 70 वर्षों से कोरियाई प्रायद्वीप और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि का आधार रहा है। गौरतलब है कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया को आरओके (रिपब्लिक ऑफ कोरिया) के नाम से संबोधित करता है। माना जा रहा है कि चो और रुबियो इस बैठक के दौरान ली-ट्रंप शिखर सम्मेलन के एजेंडा और समय निर्धारण पर भी बात कर सकते हैं।

इस बीच, कोरिया के उद्योग मंत्री किम जुंग-क्वान (जो व्यापार वार्ता प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं) ने बताया कि ट्रंप राष्ट्रपति ली से जल्द मुलाकात करना चाहते हैं और उन्होंने विदेश मंत्री रुबियो को इस बैठक को शीघ्र तय करने का निर्देश दिया है।

रूस में ऑनलाइन चरमपंथी सामग्री की तलाश भी पड़ेगी महंगी, विधेयक पर राष्ट्रपति पुतिन ने किए हस्ताक्षर

एजेंसी

मास्को। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया, जो ऑनलाइन चरमपंथी सामग्री तक पहुँचने या उसकी तलाश को अपराध घोषित करता है। इसके कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 5,000 रूबल (करीब 64 डॉलर) तक जुर्माने का प्रावधान है। यह कानून 1 सितंबर से लागू होगा। रूस की संसद के दोनों सदनों ने ऐसे विधेयक को मंजूरी दी, जिसके तहत इंटरनेट पर चरमपंथी घोषित सामग्री की तलाश अपराध माना जाएगा।दी मॉस्को टाइम्स के मुताबिक इस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया। यह कानून को रूस में इंटरनेट पर सरकारी नियंत्रण और सख्त करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर 'चरमपंथी' मानी जाने वाली सामग्री को तलाशता या एक्सेस करता है तो उस पर करीब 64 अमेरिकी डॉलर (लगभग 5000 रूबल) तक जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं किया गया है कि इसकी निगरानी किस तरह की जा सकेगी। किस तरह सर्च को ट्रैक किया जाएगा या किस आधार पर यह तय होगा कि किसने जानबूझकर ऑनलाइन ऐसी सामग्री खोजी है। रूस में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो वीपीएन का इस्तेमाल कर प्रतिबंधित साइट्स तक पहुंच बनाते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ही वीपीएन सेवाओं के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने वाले एक और विधेयक पर हस्ताक्षर किए, जो पिछले तीन वर्षों में रूस में व्यापक हो गए हैं। साल 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस में सरकार विरोधी आवाजों को दबाने के लिए ऑनलाइन सेंसरशिप और मीडिया बैन में इजाफा हुआ है।

बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने लापता बुजुर्ग की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पाकिस्तान के विदेश, गृह मंत्रालय के सचिव को तलब किया

एजेंसी

क्वेटा। बलूचिस्तान उच्च न्यायालय ने बुजुर्ग नागरिक वाहिद कंबर बलूच के लापता होने के संबंध में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के सचिव को तलब किया। 19 जुलाई 2024 को ईरान से कथित तौर पर उनका अपहरण कर लिया गया था। अपहरण के एक साल बाद भी उनका कोई अता-पता नहीं है। उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की सुनवाई करते हुए दोनों को अगली तारीख में पेश होने का आदेश दिया। द बलूचिस्तान पोस्ट की खबर के अनुसार, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका वाहिद कंबर बलूच की ओर से अधिवक्ता हबीब ताहिर और शारी बलूच ने दायर की है। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने पूर्व में पांच प्रतिवादियों को दिए गए नोटिसों की स्थिति के बारे में पूछताछ की। केवल दो जवाब प्रस्तुत किए गए, दोनों ही विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों की ओर से थे। एक जवाब में संकेत दिया गया कि मंत्रालय ने तेहरान स्थित पाकिस्तान के दूतावास से संपर्क किया। दूतावास ने बताया कि ईरान-इजराइल संघर्ष के कारण स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। फिर भी दूतावास ने कहा

कि जल्द से जल्द एक आधिकारिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। विदेश मंत्रालय के दूसरे जवाब में कहा गया कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

वकील ने इस पर न्यायमूर्तिआमिर राणा से आग्रह किया कि वे संबंधित विभागों पर सख्त निर्देश जारी करें और उनकी बरामदगी सुनिश्चित करने और उनकी स्थिति के बारे में आधिकारिक बयान प्राप्त करने के लिए दबाव डालें। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति राणा ने कहा कि न्यायालय तदनुसार कार्यवाही करेगा हालांकि, उच्च न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र का मुद्दा भी उठाया और सवाल किया कि क्या वह विदेशी धरती पर हुए अपहरण से जुड़े मामले में फैसला सुना सकता है। जवाब में, वकील ने तर्क दिया कि वाहिद कंबर पाकिस्तान के नागरिक हैं और अपहरण चाहे कहीं भी हुआ हो, कार्रवाई करना राज्य के नाते पाकिस्तान और न्यायपालिका का कर्तव्य है, खासकर जब मौलिक संवैधानिक अधिकार दांव पर हों न्यायमूर्ति राणा ने वकील के तर्क से सहमत होते हुए गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सचिव को अदालत में उपस्थित होने और अगली सुनवाई में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान वकील ने यह भी आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल के लापता होने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां जिम्मेदार हो सकती हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ पर संघीय सर्किट अपील न्यायालय में उठे सवाल, जजों ने आश्चर्य जताया

एजेंसी

वाशिंगटन। वाशिंगटन डीसी स्थित संघीय सर्किट अपील न्यायालय के न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के आपातकालीन शक्तियों के अभूतपूर्व उपयोग करते हुए अमेरिका के व्यापारिक साझेदार देशों पर व्यापक टैरिफ लगाने के अधिकार पर तीखे सवाल उठाए। कई न्यायाधीशों ने तो बार-बार इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि ट्रंप 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईपा) कानून का उपयोग करके टैरिफ को कैसे उचित ठहरा सकते हैं? अमेरिका ऑनलाइन अखबार पॉलिटिको की खबर के अनुसार, न्यायाधीश जिम्मी रेयना ने कहा, मेरी एक बड़ी चिंता यह है कि आईपी में टैरिफ शब्द का कहीं भी जिक्र तक नहीं है। न्यायाधीश टिमोथी डिक ने कहा, मेरे लिए यह समझना मुश्किल है कि कांग्रेस का इरादा आईपा में राष्ट्रपति को उस टैरिफ अनुसूची को रद्द करने का पूरा अधिकार देना था जिसे उसने वर्षों के गहन अध्ययन के बाद अपनाया था।अन्य न्यायाधीश इस तर्क पर सहमत दिखे कि ट्रंप ने एक ऐसे कानून का इस्तेमाल किया जिसका उद्देश्य राष्ट्रपतियों को किसी अंतरराष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए आपातकालीन शक्तियां प्रदान करना था, बल्कि कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को हड़पना था। यहां यह महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीश जिम्मी रेयना की नियुक्त ओबामा और न्यायाधीश टिमोथी डिक की नियुक्ति क्लिंटन ने की थी। खचाखच भरे न्यायालय में दो मुकदमों पर लगभग दो घंटे तक मौखिक बहस हुई। इन मुकदमों में ट्रंप के फरवरी और अप्रैल के बीच हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेशों में लगाए गए टैरिफ को चुनौती दी गई है। एक मामला निजी कंपनियों ने और दूसरा मामला 11 डेमोक्रेटिक नियंत्रित राज्यों ने दायर किया है। कुछ न्यायाधीशों ने मत व्यक्त किया कि अगर राष्ट्रपति बिना अदालतों की समीक्षा के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं (जैसा कि ट्रंप प्रशासन का दावा है और वह किसी भी आकार और अवधि के टैरिफ लगा सकते हैं) तो देश की जटिल और दीर्घकालिक व्यापार प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा अनिवार्य रूप से अनावश्यक हो जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के एक पुरानी आपातकालीन शक्ति के तहत लगाए गए टैरिफ केवल इसलिए कानूनी चुनौतियों से बच पाए, क्योंकि वे एक समस्या पर केंद्रित थे और उनकी एक स्पष्ट समाप्ति तिथि थी। सुनवाई के दौरान 11 न्यायाधीशों ने राज्यों और निजी कंपनियों के वकीलों के तर्क सुने। ओबामा के कार्यकाल में नियुक्त न्यायाधीश रिचर्ड टारंटो ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वादी ने वास्तव में उन नकारात्मक परिणामों पर ध्यान दिया है, जिनका ट्रंप प्रशासन दावा करता है।

गिलगित-बाल्टिस्तान में मूसलाधार बारिश से तबाही, 10 लोगों की मौत

एजेंसी

इस्लामाबाद । पाकिस्तान-अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। तेज बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लापता हैं। स्थानीय प्रशासन ने 37 बुरी तरह प्रभावित इलाकों में आपातकाल घोषित कर दिया है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बाढ़ से पर्यटन और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। अब तक अनुमानित 20 अरब रुपए से अधिक की संपत्ति को नुकसान हुआ है।

जारी अधिसूचना के अनुसार, डायमर जिले के 12, गिलगित के 9, घिजर के 5, स्कर्दू और शिगर के 4-4, गांचै के 2 और नगर व खरमंग जिलों के 1-1 क्षेत्र को आपदा प्रभावित घोषित किया गया है। अधिसूचना में कहा गया, मॉनसून

2025 के दौरान हुई भारी बारिश के चलते गिलगित, घिजर, नगर, दीमर, स्कर्दू, गांचै, शिगर और खरमंग जिलों के कई मौज़ों में बाढ़ ने गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इनमें मानव जीवन, मवेशियों, घरों, बुनियादी ढांचे और खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय अधिकारी फैजुल्लाह फराज के अनुसार, अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे। चार अन्य घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी गई है।

इस बीच, पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग (पीएमडी) ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बाढ़ की चेतावनी जारी की है। पूर्वानुमान के अनुसार, पंजाब, खैबर-पख्तूनख्वा, उत्तर-पूर्वी बलूचिस्तान, पाकिस्तान-अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, इस्लामाबाद में 40 प्रतिशत बारिश और तूफान की संभावना जताई गई है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में बारिश ने जमकर तबाई मचाई है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को मौत हुई हैं और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है।

हमास ने की स्थायी समाधान की अपील, कहा- युद्ध समाप्त करना 'मानवीय और नैतिक कर्तव्य'

एजेंसी

न्यूयॉर्क/गाजा। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल-फिलिस्तीन मुद्दे पर हुए हालिया अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के बाद फिलिस्तीनी संगठन हमास ने एक बयान जारी कर कहा है कि गाजा में युद्ध का अंत करना एक मानवीय और नैतिक कर्तव्य है।हमास ने बयान में कहा कि हम अपने फिलिस्तीनी लोगों और उनके वैध अधिकारों के समर्थन में किए गए किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रयास की सराहना करते हैं और उसका स्वागत करते हैं।

हालांकि हमास ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक इजराइल गाजा पर अपना हमला बंद नहीं करता, तब तक किसी भी राजनीतिक समाधान की कोई संभावना नहीं है। उसने इजराइल पर नरसंहार और व्यवस्थित भुखमरी नीति अपनाने का आरोप लगाया।हमास ने संकेत दिया कि वह युद्ध को समाप्त करने और इजराइली बंदियों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए एक स्थायी संघर्षविराम समझौते की जरूरत है। जिसमें गाजा से इजराइली सेनाओं की पूर्ण वापसी, सीमा पारियों (क्रॉसिंग्स) को खोलना और पुनर्निर्माण कार्यों की तत्काल शुरुआत शामिल हो। हमास ने अपने बयान में दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करते हुए कहा कि ÷हमें एक ऐसे राजनीतिक रास्ते की ओर बढ़ना होगा जो कब्जे के अंत की ओर ले जाए और हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करे, जिसमें यरुशलम को राजधानी बनाकर एक पूर्ण संप्रभु स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना हो।

अवामी एक्शन कमेटी नेता की 'ऑनर किलिंग', मानवाधिकार आयोग ने जताई कड़ी आपत्ति

एजेंसी

इस्लामाबाद । पाकिस्तान अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान (पीओजीबी) के तंगिर जिले में अवामी एक्शन कमेटी के उपाध्यक्ष जावेद नाजी और एक विवाहित महिला की 'ऑनर किलिंग' के नाम पर निर्मम हत्या कर दी गई। इस वारदात की मानवाधिकार आयोग पाकिस्तान (एचआरसीपी) ने कड़ी निंदा की है और इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करार दिया है। एचआरसीपी ने अपने बयान में कहा, 'जावेद नाजी की हत्या उनकी मां और पत्नी की आंखों के सामने की गई, जो इस बर्बरता की पराकाष्ठा है। यह तंगिर जिले में एक हफ्ते के भीतर दूसरा ऐसा मामला है, जिसमें दो पुरुषों और दो महिलाओं को इज्जत के नाम पर मार दिया गया है। आयोग ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि

इस मामले की तत्काल, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की जाए, दोषियों को कड़ी सजा दी जाए और ऑनर किलिंग की संस्कृति को जड़ से खत्म किया जाए। एचआरसीपी की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में अब तक पाकिस्तान में 405 ऑनर किलिंग के मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में अधिकतर महिलाएं ही शिकार बनी हैं, जिन्हें अपने ही परिजनों की ओर से परिवार की इज्जत के नाम पर मारा गया। हाल ही में, बलूचिस्तान में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां एक स्थानीय कबायली पंचायत के आदेश पर एक जोड़े को मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि उन्होंने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। इस घटना के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था। वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए आसिफ ने पीड़ितों की बजाय बलूच समुदाय को ही दोषी ठहराया और कहा, जुल्म करने वाले तो आपके अपने ही भाई हैं। बलूच कार्यकर्ताओं ने मंत्री के बयान को शर्मनाक और अफसोसजनक बताते हुए कहा कि मंत्री सरकार की नाकामी और कानून व्यवस्था की लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत समेत 60 देशों पर अमेरिकी टैरिफ सात अगस्त से होगा प्रभावी,ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए

एजेंसी

वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने भारत समेत 60 से अधिक अमेरिकी व्यापारिक साझेदार देशों के निर्यात पर नए टैरिफ (शुल्क) की घोषणा की। शुल्क की यह दर 07 अगस्त से प्रभावी होगी। इसमें भारत पर 25 फीसद और पाकिस्तान पर 19 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप ने वैश्विक व्यापार को फिर से पटरी पर लाने की अपनी क्रांतिकारी योजना को आगे बढ़ाते हुए आधीरात से कुछ पहले इस आशय के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।द न्यूयॉर्क टाइम्स, सीबीएस न्यूज और एनबीसी न्यूज की खबर के अनुसार, 60 से अधिक देशों पर टैरिफ 07 अगस्त की रात 12:01 बजे से प्रभावी होगा। इसका अपवाद सिर्फ कनाडा है, जिसके निर्यात पर 01 अगस्त की रात 12:01 बजे से टैरिफ लागू होगा। कनाडा पर लगने वाले टैरिफ में उन सभी वस्तुओं को छूट दी गई है, जिनका व्यापार अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते के तहत होता है। इस समय कनाडा से अमेरिका के आयात का बड़ा हिस्सा इन्हीं वस्तुओं का है। कार्यकारी आदेश में कुछ ऐसे देश भी शामिल हैं जिन्होंने प्रशासन के साथ व्यापार समझौते तोड़ दिए हैं और दर्जनों ऐसे देश हैं जिनके बीच अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। सीरिया के लिए यह शुल्क 41 फीसद, लाओस, म्यांमार के लिए 40 फीसद तक हैं। कार्यकारी आदेश में साफ किया गया है कि किसी भी देश के आयात पर 10 प्रतिशत से कम टैरिफ नहीं लगेगा।सनद रहे ट्रंप ने पहले एक अगस्त की मध्यरात्रि के बाद से उच्च शुल्क लगाने की प्रतिज्ञा की थी। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि अतिरिक्त सात दिनों की मोहलत देने का उद्देश्य सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा को नई टैरिफ दरों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय देना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 90 से अधिक देशों पर मुक्ति दिवस पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। बाद में उसे 90 दिन के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद उन्होंने व्यापार समझौतों के लिए आखिरी समय-सीमा अप्रैल में तय की। फिर 09 जुलाई की समय-सीमा आई और चली गई। व्हाइट हाउस ने फिर मोहलत दी। इसके बाद ट्रंप ने अधिकतर देशों के लिए आखिरी समय-सीमा पहली अगस्त तय की। गुरुवार की हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश की सूची में लगभग 70 व्यापारिक साझेदार शामिल हैं। जो देश सूची में नहीं हैं, उनके उत्पादों पर 10 फीसद टैरिफ लगेगा।

ईरान की बढ़ती खुफिया गतिविधियों पर अमेरिका और नाटो सहयोगियों की कड़ी चेतावनी

एजेंसी

वॉशिंगटन। अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर ईरान पर यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बढ़ते खतरों के लिए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ईरान से स्पष्ट रूप से कहा है कि वह विरोधियों, पत्रकारों, यहूदी नागरिकों और पूर्व/वर्तमान अधिकारियों को निशाना बनाने की अपनी खुफिया गतिविधियां तुरंत बंद करे। जारी इस संयुक्त बयान में कहा गया कि हम ईरानी खुफिया एजेंसियों द्वारा यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लोगों की हत्या, अपहरण और उत्पीड़न के प्रयासों का एकजुट होकर विरोध करते हैं। यह हमारी संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है।बयान में यह भी उल्लेख किया गया कि ईरानी खुफिया एजेंसियां अब अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि वे पत्रकारों, यहूदी नागरिकों और असहमति जताने वालों को निशाना बना सकें – जिसे पूर्णतः अस्वीकार्य बताया गया। बयान में चेतावनी दी गई है कि ऐसे किसी भी हमले को हमारी संप्रभुता का उल्लंघन माना जाएगा, और हम सब मिलकर इन षड्यंत्रों को नाकाम करने के लिए काम करेंगे। किन देशों ने किया हस्ताक्षर इस संयुक्त बयान पर अमेरिका और नाटो के 13 सदस्य देशों अल्बानिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, स्पेन, स्वीडन और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रिया, जो नाटो का सदस्य नहीं है।

भारतीय हाई कमिश्नर ने साइप्रस के पर्यटन मंत्री से की मुलाकात, सीधी उड़ान को लेकर हुई बात

एजेंसी

निकोसिया । भारत और साइप्रस के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इसी कड़ी में भारत के हाई कमिश्नर (उच्चायुक्त) मनीष ने निकोसिया में साइप्रस के उप पर्यटन मंत्री कोस्टास कूमिस से मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पर्यटन सहयोग को और बढ़ाना था। बैठक में दोनों पक्षों ने विशेष पर्यटन पहलों के माध्यम से सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। साथ ही यह भी विचार किया गया कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवाएं शुरू करने के लिए एयरलाइंस को किस तरह से जोड़ा जा सकता है। इस बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि दोनों देशों के बीच संपर्क को और गहरा किया जाएगा। सांस्कृतिक आदान-प्रदान और ऐतिहासिक विरासत के माध्यम से रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में गंभीर चर्चा हुई। भारत के साइप्रस स्थित उच्चायोग ने अपने एक्स पोस्ट में जानकारी दी, उच्चायुक्त मनीष ने साइप्रस के उप पर्यटन मंत्री कोस्टास कूमिस से मुलाकात की और पर्यटन सहयोग को बढ़ाने के लिए विशेष पहलों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने की संभावनाओं पर भी बातचीत हुई। पोस्ट में आगे कहा गया, भारत और साइप्रस के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी के बीच, इस बैठक में द्विपक्षीय पर्यटन को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक आदान-

प्रदान और फिल्म निर्माण में संभावित सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में दोनों देशों के बीच लोगों के स्तर पर रिश्तों को मजबूत करने, आपसी पहचान को बढ़ावा देने और ऐतिहासिक संवाद के माध्यम से रिश्तों को गहरा करने की प्रतिबद्धता दिखाई दी। जून महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडूलाइड्स से विस्तृत बातचीत की थी। इस बातचीत में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों नेताओं ने पर्यटन बढ़ाने और भारत-साइप्रस के बीच सीधी हवाई सेवा की संभावनाओं पर भी बात की थी दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक और जन-जन के संपर्क को बढ़ावा देने को विशेष महत्व दिया। साथ ही 2025 के अंत तक मोबिलिटी पायलट प्रोग्राम अरेंजमेंट को अंतिम रूप देने पर सहमति बनी।

ब्रोकली की खेती

ब्रोकली देखने में फूलगोभी (Cauliflower) जैसी होती है लेकिन रंग में अंतर होता है। फूलगोभी सफ़ेद रंग की होती है जबकि Broccoli गाढ़े हरे रंग, बैंगनी और सफ़ेद रंगों में पायी जाती है। भारत के मैदानी इलाकों में जाड़ों में और ठंडे क्षेत्र जैसे उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में इसकी खेती होती है। ब्रोकली गोभी साधारण गोभी से काफी Costly मिलती है। बड़े महानगरों, होटलों में इनकी काफी मांग है। ब्रोकली मुख्यत: Italy का पौधा है। ब्रोकली कई यूरोपीय खानों और Salad बनाने में प्रयोग की जाती है।

ब्रोकली के फायदे

1) ब्रोकली में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट, विटामिन, विटामिन C, विटामिन Bv,Bw, Bx, B, पोटैशियम, मैगनिशियम, जिंक, फास्फोरस, एंटीओक्सिडेंट होते हैं। ब्रोकली कच्ची और उबाल कर दोनों रूप में खाई जा सकती है। ये रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और शरीर को कई आवश्यक पोषक तत्व देता है।

2) गर्भवती महिलाओं के लिए ब्रोकली बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला आयरन, फोलेट बच्चे के दिमागी और शारीरिक विकास के लिए अच्छा होता है।

3)Broccoli का बीटाकैरटिन मोतियाबिंद, मस्कुलर डिजनरेशन रोकता है। ब्रोकली में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल और सल्फोरोफेन तत्व कैंसर की बीमारी से शरीर का बचाव करता है।

4) ब्रोकली महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हॉर्मोन का स्तर नियंत्रित करती है। एस्ट्रोजन हॉर्मोन बढ़ने से गर्भाशय कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। ब्रोकली का सेवन इन समस्याओं से बचाव करता है।

5) ब्रोकली में विटामिन K होता है जोकि खून बहने पर रक्तस्राव रोकने में मदद करता है। Broccoli में पाए जाने वाला विटामिन ष्ट कोलेजन बॉडी टिश्यू, हड्डी बनाता है जोकि घाव भरने, स्किन को युवा बनाये रखने में मदद करता है।

6) ब्रोकली में खूब फाइबर होता है जोकि पाचन तन्त्र स्वस्थ रखता है, मोटापा कम करता है। हाई फाइबर शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल कम करता है, जोकि ह्रदय धमनियों को स्वस्थ रखकर हार्ट की बीमारी से बचाता है।

7) वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि ऐसे मोटे लोग जोकि टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं, उन्हें ब्रोकली का सेवन ब्लड शुगर लेवल कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ब्रोकली आटिज्म रोगियों के व्यवहार और सम्वाद समस्या के असर को कम करता है।

8) Broccoli का कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाकर ओस्टियोपोरोसिस बीमारी का खतरा कम करता है और आयरन एनीमिया की बीमारी से बचाता है। इसका सेवन बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती स्त्रियों के लिए खास फायदेमंद है।

9) ब्रोकली झुर्रियाँ, फाइन लाइन्स जैसी समस्या दूर कर चेहरे और शरीर की स्किन पर बढ़िया असर डालता है। इसका विटामिन ष्ट, कॉपर, जिंक स्किन को ग्लो और टाइटनेस देते हैं। ब्रोकली के एंटीओक्सिडेंट फ्री रेडिकल्स को नष्ट करके बढती उम्र के लक्षणों को कम करते हैं।

10) ब्रोकली में पाए जाने वाले फाइटोन्यूट्रीएंट्स जैसे तत्व शरीर को Deto& करके कई रोगों को पैदा होने से रोकते हैं और रक्त शुद्ध करते हैं। Broccoli Weight Loss करने में असरकारक है। ये हाई फाइबर और प्रोटीन युक्त है, जिससे भूख जल्दी नहीं लगती, कब्ज दूर होता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है।

Broccoli को बहुत अधिक उबालने से उसके कैंसर रोधी गुण कम हो जाते हैं। 20 मिनट से अधिक भाप देने, 3 मिनट से अधिक माइक्रोवेव में रखने और 5 मिनट से अधिक फ्राई करने से ब्रोकली के कैंसररोधी गुण कम होते हैं। अत: अधिकतम फायदों के लिए ब्रोकली को इन समय सीमा के अंदर ही पकाएं। कच्ची ब्रोकली सभी गुणों से भरपूर होती है, लेकिन बहुत अधिक खाने से गैस और अपच की समस्या हो सकती है।

ज्यादा मुनाफे के लिए करें ब्रोकली की खेती

ब्रोकोली की खेती ठीक फूलगोभी की तरह की जाती है। इसके बीज व पौधे देखने में लगभग फूल गोभी की तरह ही होते हैं। लेकिन इसका रंग हरा होता है इसलिए इसे हरी गोभी भी कहते है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में इन सब्जियों की खेती बड़ी सुगमता पूर्वक की जा सकती है जबकि हिमाचल प्रदेश , उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर में में इनके बीज भी बनाए जा सकते है। सब्जियों की पैदावार में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। लेकिन आज भी हमारी ज्यादातर सब्जियों की कम उत्पादकता व कमजोर गुणवत्ता की । आगे आने वाले समय में सब्जियों का उत्पादन व विदेशों में उन की सप्लाई दोनों ही बढ़ सकते हैं। इस तरह की सब्जियों में ब्रोकली का नाम बहुत मशहूर है. इस की खेती पिछले कुछ सालों से धीरेधीरे बड़े शहरों के आसपास कुछ किसान करने लगे हैं। बड़े महानगरों में इस सब्जी की मांग भी अब बढ़ने लगी है । पांच सितारा होटलों व पर्यटक स्थानों पर इस सब्जी की मांग बहुत है और जो किसान इस की खेती कर के इस को सही बाजार में बेचते हैं, उन को इस की खेती से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। पांच सितारा होटल तथा पर्यटक स्थानों पर इस सब्जी की मांग बहुत है तथाजो किसान इसकी खेती करके इसको सही बाजार में बेचते हैं उनको इसकी खेती से बहुत अधिक लाभ मिलता है क्योंकि इसके भाव कई बार 30 से 50 रुपये प्रति कि.ग्रा. तक या इससे भी उपर मिल जाते हैं। यहां ये बताना उचित रहेगा कि ब्रोकोली की खेती करने से पहले इसको बेचने का किसान जरूर प्रबंध कर लें क्योकि यह अभी महानगरों, बड़े होटल तथा पर्यटक स्थानों तक ही सीमित है। साधारण, मध्यम या छोटे बाजारों में अभी तक ब्रोकोली की मांग नहीं है। बाजार में ब्रोक्कोली की कीमत सामान्य गोभी से कहीं ज्यादा है. बड़े शहरों में बाजारों इसकी कीमत 100 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति किलो होती है. बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखण्ड जैसे कई प्रदेशों में इसकी आयात दिल्ली और पुने जैसे बड़े शहरों से होने के कारण इसकी कीमत और बढ़ जाती है. तो छोटे शहरों के किसानों के पास अच्छा अवसर है की वो अपने लोकल मार्केट में ही अच्छे दामों पर ये फसल बेच सकते हैं. मांग बढ़ने पर निर्यात कर के आमदनी और बढ़ाई जा सकती है. उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में ब्रोकोली उगाने का उपयुक्त समय ठण्ड का मौसम होता है इसके बीज के अंकुरण तथा पौधों को अच्छी वृद्धि के लिए तापमान 20 -25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इसकी नर्सरी तैयार करने का समय अक्टूम्बर का दूसरा पखवाडा होता है पर्वतीय क्षेत्रों में कम उचाई वाले क्षेत्रों में सितम्बर- अक्टूम्बर , मध्यम उचाई वाले क्षेत्रों में अगस्त सितम्बर, और अधिक उचाई वाले क्षेत्रों में मार्च- अप्रैल में तैयार की जाती है ।

शोभाकारी पौधों का रख-रखाव कैसे करें

सदाबहार एपोसाइनेसी कुल का एक शाकीय पौधा है। अंग्रेजी में इसका नाम पेरिविंकल है। इसे सदा-सुहागिन भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यदि एक बार इसका पौधा लगा दिया जाए तो इसमें हर मौसम में वर्षभर थोड़े-बहुत फूल हमेशा खिलते रहते हैं।

ग्रीष्म ऋतु आते ही मनुष्य रुखापन महसूस करने लगता है। इस कारण उसका रुझान हरियाली की ओर होने लगता है। ऐसे समय में बाग-बगीचों के उद्यानों की हरी घास पर बैठ कर समय बिताने का मन करता है। हरे-भरे पौधों को देखने की इच्छा होती है, इससे मन को शांति मिलती है तथा मानसिक तनाव भी दूर होता है। इसके अतिरिक्त प्रदूषित पर्यावरण से दूर रह कर हरियाली के बीच में रहना स्वास्थ्यवर्धक होता है। हरियाली के साथ यदि कुछ रंग-बिरंगे फूलों का भी संगम हो जाए तो चित्त और भी प्रसन्न हो उठता है।

इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रीष्म ऋतु में होने वाले कुछ प्रमुख शोभाकारी पौधों का रख-रखाव कैसे करें, इसकी जानकारी इस लेख में दी जा रही है।

गर्मी के मौसम में बगीचों, पार्कों और अपने आस-पास के वातावरण को हरा-भरा रखने तथा हरियाली का आनंद लेने के लिए सर्वोत्तम पौधा कोचिया है। कोचिया पत्तियों की सुंदरता वाला एक सजावटी पौधा है। यह शाकीय होता है, जो 'चिनोपोडिएसी' कुल से संबंधित है। इसका पौधा 2-3 फुट की ऊंचाई तथा 175 फुट की चैड़ाई तक फैलता है

कोचिया का पौधा सुंदर, मनमोहक और बड़ा ही शोभावर्धक होता है। यह गुंबज जैसी आकृति का होता है, जो नीचे से ऊपर तक हल्के हरे रंग की पतली लंबी घनी पत्तियों से भरा रहता है। पत्तियों पर हाथ फेरने से लगता है मानो किसी मुलायम गलीचे पर हाथ फेर रहे हों। कोचिया का वानस्पतिक नाम, 'कोचिया स्कापैरिया' है। इसका दूसरा नाम 'कोचिया ट्राइकोफाइला' भी है। अंग्रेजी में कोचिया को 'समर साइप्रेस' तथा बर्निंग बुश कहते हैं। साइप्रेस (क्यूप्रेसस सेंपरवाइरेंस) एक सदाबहार गुंबजाकार पौधा है, जिसे हिंदी में 'सरो' कहते हैं। इसकी हरी-पतली कटी हुई पत्तियां बड़ी सुंदर होती हैं। चूंकि कोचिया के पौधे की आकृति इससे मिलती-जुलती है परंतु इसे गर्मी के मौसम में ही उगाते हैं, इसलिए अंग्रेजी में इसको समर साइप्रेस का नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसका पौधा एक छोटे से मीनार की भांति खड़ा रहता है, जो उतार-चढ़ाव सहित ढालू आकार का होता है, इसलिए इसे 'बेलबेडिअर बुर्ज का भी नाम दिया गया है।

गर्मी के पूरे मौसम में कोचिया के पौधे खूब हरे-भरे रहते हैं। यदि इनकी देखभाल होती रहे तो ये वर्षा ऋतु तक भी चलते रहते हैं। वर्षा ऋतु समाप्त होने से कुछ पहले इसकी पत्तियों की हरियाली में मामूली सा ताम्र रंग का अंश आ जाता है। इसके बाद पूरा पौधा लाल-बैंगनी रंग के छोटे-छोटे फूलों से भर जाता है। इसलिए अंग्रेजी में इसे 'बर्निंग बुश' का नाम दिया गया है। इसमें अधिक तापमान सहन करने की क्षमता है। कोचिया की एक और जाति है, जिसका नाम 'कोचिया चाइल्डसाइज' है। इसका पौधा अपेक्षाकृत छोटा होता है जो केवल 175-2 फुट की ऊंचाई तक वृद्धि करता है तथा यह हमेशा हरा ही रहता है।

कोचिया के पौधे जमीन में या गमलों में लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए 9-10 इंच माप के गमले प्रयोग में लाने चाहिए तथा एक गमले में केवल एक ही पौधा लगाना चाहिए। जमीन में लगाने के लिए इसे किसी कोने या कहीं एक किनारे पर अकेले या रास्तों के किनारे लगा सकते हैं। स्थायी रूप से इस पौधे को झाड़ या हेज के रूप में भी लगा सकते हैं। कोचिया की अच्छी बढ़वार के लिए खादयुक्त, उत्तम जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी तथा प्रकाशयुक्त स्थान की आवश्यकता होती है। पौधशाला में इसकी

WORLD BREASTFEEDING WEEK
1st-7th AUGUST 2025

THEME :- Prioritize Breastfeeding : Create Sustainable Support Systems

Benefits of Breastfeeding to baby:
•Boosts immunity.
•Improves physical growth.
•Enhances mental development.
•Prevents diarrhoea, ear infections, food & respiratory allergies and many more diseases.

Benefits of Breastfeeding to mother:
•Decreases postpartum bleeding.
•Lessens risk of breast cancer, ovarian cancer, osteoporosis.
•Helps to lose post pregnancy weight
•Strengthens maternal bonding with baby.

•Initiate breastfeeding within 1 hour of birth.
•Give exclusive breastfeeding for the first six months of life.
•Continue breastfeeding up to 2 years of age or beyond with introduction of nutritionally adequate and safe complementary (solid) foods at 6 months.

DIP/J-4182/25
Dtd: 1-8-2025

Directorate Of Health Services JAMMU

Health Education Bureau
Directorate of Health Services Jammu